Website: www.winews.in | Email: winews.in@gmail.com | दिल्ली, नोएडा, हापुड़, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, राजस्थान, पंजाब, बहराइच, रामपुर, लखनऊ, काशीपुर, देवबंद में प्रसारित

दैनिक वेलकम इंडिया

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 226 | बुधवार, 26 अगस्त-2026 (गाजियाबाद) | पेज-8 | मूल्य-एक रुपया

मिशन रोजगार के तहत 3572 युवाओं को नियुक्ति

चयनित अभ्यर्थियों ने सराहा योगी सरकार का पारदर्शी मॉडल

वेलकम इंडिया नेटवर्क

लखनऊ। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 3572 युवाओं को बड़ी सौगात दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में नवचयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चयनित युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से नियुक्ति पूरी कराने के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना की।

दो महीने के भीतर नियुक्ति पत्र मिलना सरकार की तेजी और कार्यप्रणाली को दशार्ता

बस्ती निवासी महिपाल सिंह का चयन कृषि प्राविधिक सहायक पद पर हुआ है और उनकी पोस्टिंग बाराबंकी में हुई है। महिपाल ने वर्तमान सरकार में चयन प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा कि 23 जून को परिणाम आने के करीब दो महीने के भीतर नियुक्ति पत्र मिलना सरकार की तेजी और कार्यप्रणाली को दशार्ता है।

रायबरेली निवासी राणा प्रताप सिंह का चयन कृषि प्राविधिक सहायक पद पर हुआ है और उनकी नियुक्ति अमेठी में हुई है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। वर्तमान सरकार में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए गौरव का विषय है।

आरक्षण नियमों का हुआ पूरी तरह पालन

बाराबंकी की महिमा मौर्या का चयन मंडी सचिव पद पर हुआ है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए कहा कि आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। महिमा ने कहा कि सीटों में किसी तरह की हेरफेर नहीं हुई और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर नियमानुसार चयन हुआ। वहीं प्राविधिक सहायक पद पर चयनित ज्ञानवी तिवारी ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और महिलाओं को भी बड़ी संख्या में अवसर मिल रहे हैं। निष्पक्ष भर्ती से युवाओं में सरकार के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है।

सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर काम कर रही

अम्बेडकर नगर निवासी साधना देवी का चयन कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक पद पर हुआ है और उन्हें अयोध्या जिले में तैनाती मिली है। उन्होंने नियुक्ति वितरण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए खुशी और गर्व का क्षण है।

नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगी

रामपुर की खुशनुमा का चयन मंडी सचिव ग्रेड-2 पद पर हुआ है। खुशनुमा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का काम हुआ है। नियुक्तियों की पारदर्शिता और महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम के संबोधन में कही गई बातों को अपने कार्यक्षेत्र में धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगी और नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगी।

प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) पद पर चयनित पवनेश कुमार ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है। योग्य युवाओं को बिना भेदभाव अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति मिलना उनके लिए गौरव और खुशी का क्षण है। पवनेश ने युवाओं से अपील की कि वे लक्ष्य तय कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करें।

मिसाइल निर्माण में बड़ी छलांग, ब्रह्मोस की रफ्तार से बढ़ेगा भारत

राजनाथ सिंह ने डीआरडीओको दिया आदेश, भारतीय उद्योगों को सौंपें अपनी उन्नत टेक्नॉजी

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को भारतीय रक्षा कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है, ताकि देश के अंदर ही इनका उत्पादन किया जा सके। इस कदम का मकसद देश में ही मिसाइल बनाने की रफ़्तार बढ़ाना, आयात पर भारत की निर्भरता कम करना और डिफेंस सप्लाई चेन में घरेलू कंपनियों (जिनमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी टरटए भी शामिल हैं) की भूमिका को बढ़ाना है। मंत्रालय ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से योग्य भारतीय उद्योगों को DRDO द्वारा विकसित पारंपरिक मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन करने की इजाजत मिलेगी, बशर्ते वे जरूरी योग्यता, सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करते हों। इस फैसले को रक्षा क्षेत्र में सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इससे मिसाइल सिस्टम को डेवलपमेंट स्टेज से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन (इंडस्ट्रियल-स्केल प्रोडक्शन) तक ले जाने में मदद मिलेगी और साथ ही भारत के घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को भी मजबूती मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना और सप्लाई चेन में भारतीय MSME और अन्य टेक्नोलॉजी पार्टनर की भागीदारी के लिए मौके बनाना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत के पड़ोसी देशों में मिसाइल क्षमताओं को बड़े पैमाने पर निगरानी, संचार और सटीक हमले वाले नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है। 'सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज' की जुलाई की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की अंतरिक्ष क्षमताओं के तेजी से विस्तार पर जोर दिया गया, खासकर चीन के साथ उसके सहयोग के जरिए। रिपोर्ट में कहा गया कि दशकों तक धीमी प्रगति के बाद, पाकिस्तान के 'स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन' ने 16 महीनों में छह सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने और सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी को जमीनी संचार प्रणालियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में बीएएमएस की फर्जी डिग्री से बने 41 डॉक्टर, बोर्ड ने एफआईआर के दिए कड़े आदेश

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने 41 ऐसे कथित फजी आयुर्वेदिक डॉक्टरों का पता लगाया है जो जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, इन डॉक्टरों ने कथित तौर पर फजी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की मार्कशीट, इंटर्नशिप सर्टिफि केट, डिग्री और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफि केट का इस्तेमाल करके आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया था। बोर्ड ने लखनऊ पुलिस को शिकायत देकर इन सभी 41 डॉक्टरों के खिलाफ त्र्क्ष्क्ष्दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, बोर्ड ने पिछले 15 सालों में रजिस्टर्ड हुए डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता और डिग्री की जांच के आदेश भी दिए हैं। अब तक हुई जांच के मुताबिक, इन 41 डॉक्टरों के पास कथित तौर पर फजी इअटर मार्कशीट, इंटर्नशिप सर्टिफि केट और डिग्री सर्टिफि केट थे, जो कथित तौर पर श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कुरुक्षेत्र और पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक के नाम से जारी किए गए थे। जांच में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा के नाम से जारी कथित फजी ठडउ भी मिली हैं। इन डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों से इलाज करने वाले डॉक्टरों के लिए राज्य सरकार के आयुष विभाग के तहत 'आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड' में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत, इन 41 डॉक्टरों ने बोर्ड को अपनी मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। रजिस्ट्रेशन देने से पहले बोर्ड ने इन डॉक्यूमेंट्स की जांच-पड़ताल भी की थी। डॉक्यूमेंट्स को जांच के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी भेजा गया था।

जनगणना में जाति गिनने के तरीके पर घमासान, खरगे-राहुल का पीएम को पत्र; पूछा- सही डाटा कैसे मिलेगा ?

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने सरकार से मौजूदा प्रश्नावली को रद्द कर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता से परामर्श के बाद नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है। खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा तरीके से हो रही जाति जनगणना उन्हें स्वीकार्य नहीं है और सरकार को तेलंगाना तथा बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों से सीख लेनी चाहिए।

25 अगस्त को पत्र को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जाति जनगणना को लेकर सरकार की मौजूदा कवायद महज 'खानापूर्ति' है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर यह तीसरा पत्र है, लेकिन अब तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। खड़गे और राहुल गांधी ने 20 अगस्त को हिंदी में यह पत्र लिखा था।

पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि भारत में सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सटीक आंकड़े बेहद जरूरी हैं। विभिन्न जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है, जब जातियों की गणना सही तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनगणना में जाति का विवरण दर्ज करने के लिए 'ओपन-एंडेड' सवालों का तरीका अपनाया है, जिसमें व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, वही दर्ज किया जाएगा।

खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि भारत में एक ही जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाई रूपों से जानी जाती है। ऐसे में यदि एक ही जाति के लोगों के नाम अलग-अलग दर्ज किए गए तो एक जाति हजारों अलग-अलग नामों में बंट सकती है। इससे जातियों के नामों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और जाति जनगणना से हासिल पूरा डेटा अनुपयोगी होने का खतरा है।

दोनों नेताओं ने कहा कि यदि किसी समुदाय की वास्तविक संख्या ही सही तरीके से दर्ज नहीं होगी तो उसकी सामाजिक स्थिति का आकलन भी गलत होगा। इसका सबसे अधिक नुकसान पिछड़े, अति पिछड़े और अन्य वंचित समुदायों को हो सकता है। इससे शिक्षा, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसले भी प्रभावित होंगे। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मौजूदा प्रक्रिया से भारत में डइउ की वास्तविक आबादी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस जनगणना में Backward Class यानी पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है।

खड़गे और राहुल गांधी ने जातियों की पहचान के लिए पहले से तैयार और प्रमाणित सूची इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना में इसी तरह की सूची का इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की मौजूदा सरकारी सूचियों तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण की सूची के आधार पर ऐसी सूची तैयार की जा सकती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को दोनों राज्यों के जाति सर्वेक्षणों में इस्तेमाल की गई सूचियों की प्रतियां भी भेजी हैं।

बांकेबिहारी मंदिर प्रबंधन को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, भक्तों का दान सीधे खजाने में जाए, गोलक" चोरी के आरोपों पर जताई नाराजगी

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को दान में मिलने वाला सारा पैसा - चाहे वह दान पेटी के जरिए हो या ऑनलाइन - सीधे मंदिर के खजाने में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेवकों या किसी और की तरफ से इसमें कोई भी रुकावट डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैनेजमेंट कमेटी को गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई उखकसूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान, वकील एनके गोस्वामी ने आरोप लगाया कि मंदिर के फंड में वित्तीय गड़बड़ी हुई है और करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम के गबन के आरोपों को गंभीरता से लिया और कहा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और हम निर्देश देते हैं कि दान का एक-एक पैसा दान-पात्रों या मंदिर के ऑनलाइन खजाने में ही जमा होना चाहिए। 'सेवायत' या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसमें कोई भी बाधा डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। प्रबंधन समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी होगी। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया।

बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव के बीच नितिन गडकरी बोले: मैं अब उतना काम नहीं कर सकता, युवा संभालें कमान

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब नई पीढ़ी को ज़िम्मेदारियाँ सौंपने का समय आ गया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी कम हुई है और अब युवा पीढ़ी को काम को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की बढ़ती चचाओं के बीच आई है। गडकरी ने बताया कि कैसे रोजमर्रा के कामों में उनकी भागीदारी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि काम नई पीढ़ी को सौंप दिया जाना चाहिए। एक नई पीढ़ी आ गई है और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन कर रही है। गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई पुरस्कार भी पाए हैं।

लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, गडकरी ने आगे के विकास कार्यों के बारे में भी बात की और कहा कि आने वाले सालों में काम का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मकसद यह पक्का करना है कि महाराष्ट्र का कोई भी आदिवासी गांव बिजली से वंचित न रहे और पूरे राज्य में विकास साफ तौर पर दिखे। केंद्रीय मंत्री की ये बातें बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के कुछ ही दिनों बाद सामने आईं। 2015 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद से यह इस स्तर का पहला बदलाव था। पिछले हफ़्ते, बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे शामिल हैं, जो संगठन में पीढ़ीगत बदलाव का बड़ा संकेत है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी राम माधव शामिल हैं।

लिस्ट से बाहर किए गए वोटर्स का क्या होगा ? बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से मांगा पूरा ब्योरा

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने को चुनौती देने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित और निपटाए गए अपीलों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन अपीलों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि लंबित अपीलों के निपटारे के तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है।

पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक जवाब दाखिल कर स्पष्ट करे कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कितनी अपीलें लंबित हैं। लंबित अपीलों को अलग-अलग श्रेणी में रखा जाए, और यह बताया जाए कि मतदाता सूची से बाहर किए गए या शामिल किए गए मतदाताओं की ओर से कितनी अपीलें की गई हैं और क्रॉस-अपीलें कितनी हैं। कोर्ट ने कहा कि आयोग यह भी स्पष्ट करे कि कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल गठित किए जाने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि लोगों को इस बात का कोई डेटा नहीं मिल पा रहा है कि ट्रिब्यूनल के पास कितनी अपीलें लंबित हैं या कितनों पर फैसला सुनाया जा चुका है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

बनर्जी ने कहा कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव करीब हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, वे वोट नहीं डाल पाएंगे। मैंने 31 विधानसभा सीटों का डेटा कोर्ट को दिया है। कृपया चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगें कि कितनी अपीलें दायर की गई हैं और कितनों का निपटारा किया गया है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को केवल 31 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेगी। पीठ ने कहा, 'हमारी चिंता सभी क्षेत्रों को लेकर होगी। अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा होना आवश्यक है। यदि आवश्यकता पड़ी, तो हम और अधिक ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे।' अन्य याचिकाकताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने एक सांसद को दिए गए आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए इस जानकारी को भयावह बताया। उन्होंने कहा कि रक्ष्क्ष् अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की गई बड़ी संख्या में अपीलें वास्तव में उन मतदाताओं द्वारा नहीं की गई हैं जिन्हें सूची से बाहर किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग अपीलीय ट्रिब्यूनल के साथ समन्वय कर रहा है ताकि अपीलों के निपटान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के तरीकों की जांच की जा सके। यह सुनवाई रक्ष्क्ष् अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलों के निपटारे में तेजी लाने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की मांग वाली याचिकाओं पर हो रही थी। इससे पहले 24 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने अपीलीय ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल में रक्ष्क्ष्के बाद मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ जो लोग तत्काल सुनवाई का मजबूत आधार रखते हैं, उन्हें आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई का अवसर दिया जाए। लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों ओडिशा तथा झारखंड से लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया था।

संपादक की कलम से

विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

ललित शर्मा
संपादक

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यदि हम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है-ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024-25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब 33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कहानी है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बैठकर भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक है और कक्षाएं पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली और पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वर्षों से चली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में दी गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है-फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024-25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023-24 के 1,10,971 से घटकर 2024-25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है।

आरक्षण के जबड़े में दम तोड़तीं शैक्षणिक उपलब्धियां

एनके शर्मा
लेखक

भारत की शिक्षा-व्यवस्था आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहाँ एक ओर प्रतिभा, परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टि और उत्कृष्टता का सपना है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक वंचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जटिल वास्तविकता। इसी द्वंद्व के बीच आरक्षण व्यवस्था को लेकर देश में एक ऐसा विमर्श खड़ा हो गया है, जिसमें तर्क से अधिक भावनाएं, नीति से अधिक राजनीति और समाधान से अधिक आरोप दिखाई देते हैं। आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर उपलब्ध कराना था; लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दशकों बाद भी इसकी संरचना, सीमा, लाभार्थियों की पहचान और समीक्षा के मानदंड उतने ही प्रभावी हैं, जितने होने चाहिए? यदि व्यवस्था का लक्ष्य समान अवसर है, तो उसकी सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि वंचित व्यक्ति ऊपर उठे-न कि वंचना पीढ़ी-दर-पीढ़ी राजनीतिक संसाधन बनी रहे।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता को समझने के लिए इतिहास से आंखें चुराना संभव नहीं। सदियों तक सामाजिक भेदभाव, शिक्षा से वंचितता और अवसरों की असमानता ने समाज के बड़े वर्गों को पीछे धकेला। संविधान निमार्ताओं ने इसी ऐतिहासिक अन्याय को ध्यान में रखते हुए समानता को केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए आरक्षण को केवल 'योग्यता बनाम आरक्षण' के संकुचित चश्मे से देखना भी अन्यायपूर्ण होगा। समस्या आरक्षण के अस्तित्व से कम और उसकी राजनीति, उसकी निरंतरता, उसके क्रियान्वयन तथा उसके परिणामों के निष्पक्ष मूल्यांकन से अधिक जुड़ी हुई है। सबसे गंभीर प्रश्न तब उठता है जब सामाजिक न्याय के नाम पर ऐसी व्यवस्था विकसित हो जाए जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक वास्तविकताओं का सूक्ष्म मूल्यांकन पीछे छूट जाए और राजनीतिक गणित सर्वोपरि हो जाए। लोकतंत्र में संख्या शक्ति का महत्व है, लेकिन यदि हर सामाजिक समूह को केवल चुनावी गणित के रूप में देखा जाने लगे तो कल्याणकारी नीति धीरे-धीरे वोट बैंक की रणनीति बन जाती है। फिर आरक्षण सामाजिक उत्थान का साधन कम और राजनीतिक घोषणाओं का हथियार अधिक दिखाई देने लगता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण है। भारत आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। ऐसे समय में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिभा का अधिकतम विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसलिए प्रवेश और अवसर की नीतियों को इस तरह निरंतर परिष्कृत करना होगा कि सामाजिक न्याय और शैक्षणिक उत्कृष्टता एक-दूसरे के विरोधी न बनें। सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को यह महसूस होने लगे कि उसकी मेहनत का मूल्यांकन उसके ज्ञान और क्षमता से अधिक उसकी सामाजिक पहचान के आधार पर होगा। यह भावना केवल व्यक्तिगत निराशा नहीं पैदा करती; यह व्यवस्था में विश्वास को भी कमजोर कर सकती है। दूसरी ओर, वंचित वर्ग का विद्यार्थी यदि यह महसूस करे कि उसे केवल आरक्षण के कारण 'कमतर' समझा जा रहा है, तो यह भी उतना ही घातक है। इसलिए असली लड़ाई आरक्षण पाने वाले और न पाने वाले विद्यार्थियों के बीच नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ होनी चाहिए जो दोनों में अविश्वास पैदा करती है। आरक्षण की आलोचना करते समय एक और कठोर सत्य स्वीकार करना होगा-सिर्फ आरक्षण समाप्त कर देने से असमानता समाप्त नहीं होगी। यदि किसी गरीब बच्चे के पास गुणवत्तापूर्ण स्कूल नहीं है, उसके परिवार के पास महंगी कोचिंग का खर्च नहीं है, डिजिटल संसाधन नहीं हैं और उसे पौष्टिक भोजन तक उपलब्ध नहीं, तो केवल परीक्षा के दिन उससे समान प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा करना भी न्याय नहीं है। समान अवसर का अर्थ केवल परीक्षा-कक्ष में समान प्रश्नपत्र देना नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए समान रूप से सक्षम बनाना भी है। यहीं भारत की नीति-व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता दिखाई देती है। यदि सरकारें वास्तव में सामाजिक न्याय चाहती हैं, तो प्राथमिक शिक्षा, सरकारी विद्यालयों, शिक्षक गुणवत्ता, छात्रवृत्ति, पोषण, डिजिटल पहुंच, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और ग्रामीण शिक्षा के स्तर को इतना मजबूत क्यों नहीं किया जाता कि आरक्षण पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो? किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि उसने कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं; बल्कि यह है कि उसने कितने वंचित बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि वे बिना किसी विशेष सहारे के भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। राजनीति ने दुर्भाग्य से इस प्रश्न को और जटिल बना दिया है। जातीय पहचानें चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बनती हैं, समुदायों को आश्वासन दिए जाते हैं और आरक्षण की मांगें राजनीतिक दबाव का माध्यम बन जाती हैं। परिणाम यह है कि सामाजिक न्याय की गंभीर अवधारणा कई बार चुनावी घोषणापत्र के एक वाक्य में सिमट जाती है। जिस नीति का उद्देश्य सामाजिक विभाजन कम करना था, वही यदि पहचान की राजनीति को स्थायी बना दे, तो हमें ठहरकर पूछना होगा कि कहीं साधन ही लक्ष्य तो नहीं बन गया? आरक्षण के भीतर भी असमानता का प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि किसी आरक्षित वर्ग के भीतर अपेक्षाकृत सक्षम और संसाधन-संपन्न परिवार बार-बार लाभ प्राप्त करते रहें और उसी वर्ग के अत्यंत गरीब, दूरदराज और पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों तक अवसर न पहुंचे, तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए किसी भी आरक्षण व्यवस्था का समय-समय पर तथ्यात्मक, पारदर्शी और स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है। कौन लाभान्वित हुआ? कौन अब भी पीछे है? किन क्षेत्रों में अवसर नहीं पहुंचे? किस स्तर पर आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अधिक है? इन प्रश्नों के उत्तर आंकड़ों से मिलने चाहिए, नारों से नहीं। यह भी आवश्यक है कि 'मेरिट' शब्द की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया जाए। प्रतिभा केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों का नाम नहीं; लेकिन अंक और योग्यता को पूरी तरह अप्रासंगिक बना देना भी खतरनाक है। उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन ही स्वस्थ नीति का आधार होना चाहिए। ऐसे मॉडल विकसित किए जा सकते हैं जिनमें आर्थिक कठिनाई, विद्यालय की गुणवत्ता, भौगोलिक पिछड़ापन, सामाजिक वंचना और शैक्षणिक प्रदर्शन-सभी का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो। इससे सहायता उन लोगों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकती है जिन्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता है। भारत को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आरक्षण स्थायी राजनीतिक पहचान नहीं, बल्कि सामाजिक गतिशीलता का पुल बने। लक्ष्य यह होना चाहिए कि एक दिन ऐसा समाज बने जहां किसी बच्चे की संभावनाएं उसकी जाति, जन्मस्थान या परिवार की आर्थिक स्थिति से तय न हों। लेकिन उस आदर्श तक पहुंचने के लिए केवल आरक्षण की बहस पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा में क्रांतिकारी निवेश, सरकारी विद्यालयों के पुनर्निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध के विस्तार और गरीब विद्यार्थियों के लिए व्यापक सहायता की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा खतरा आरक्षण नहीं, बल्कि आरक्षण को लेकर समाज का स्थायी ध्रुवीकरण है। जब एक वर्ग स्वयं को अवसरों से वंचित समझता है और दूसरा वर्ग अपनी पहचान को लगातार असुरक्षित महसूस करता है, तब सामाजिक विश्वास कमजोर होता है। और जिस राष्ट्र में सामाजिक विश्वास कमजोर हो जाए, वहां आर्थिक विकास भी असमानता, संघर्ष और असंतोष के बोझ तले दबने लगता है। इसलिए आरक्षण पर बहस न तो अंध-समर्थन की होनी चाहिए और न अंध-विरोध की। प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या वर्तमान व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य-समान अवसर और सामाजिक न्याय-को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर रही है? यदि नहीं, तो सुधार क्यों नहीं? नीतियां संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं, लेकिन उनकी वैधता उनके परिणामों से मजबूत होती है। भारत को जातियों की स्थायी दीवारों से बाहर निकलकर अवसरों का ऐसा लोकतंत्र बनाना होगा जहां गरीब का बच्चा भी वैज्ञानिक बने, किसान का बेटा भी प्रोफेसर बने, श्रमिक की बेटी भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने और किसी प्रतिभा को अपनी पहचान के कारण न तो अपमानित होना पड़े और न किसी विशेषाधिकार का स्थायी सहारा लेना पड़े। आरक्षण सामाजिक न्याय की यात्रा का एक साधन हो सकता है, मंजिल नहीं। यदि राजनीति इसे अपनी सत्ता का स्थायी ईंधन बना देगी, तो यह व्यवस्था समाज के घाव भरने के बजाय उन्हें कुरेदती रहेगी।

महंगा इलाज, भारी पड़ती जिंदगी

डॉ विजय गर्ग
लेखक

स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, तो उसकी पहली चिंता समय पर और उचित उपचार प्राप्त करना होती है। लेकिन आज लाखों परिवारों के लिए चिकित्सा खर्च गहरी चिंता का कारण बन गया है। महंगी दवाइयाँ, जांच, अस्पताल के शुल्क, सर्जरी और लंबे समय तक चलने वाला उपचार परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। कई लोगों के लिए संघर्ष केवल बीमारी से नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाले आर्थिक बोझ से भी होता है।

चिकित्सा विज्ञान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जिन बीमारियों को कभी लाइलाज माना जाता था, उनमें से कई का आज उपचार या प्रभावी प्रबंधन संभव है। अत्याधुनिक सर्जरी, आधुनिक जांच तकनीक, विशेष दवाइयाँ और गहन चिकित्सा सुविधाएँ अनगिनत जीवन बचाने में सहायक बनी हैं। लेकिन इन प्रगतियों की कीमत भी कई बार बहुत अधिक होती है। अत्याधुनिक उपचार की उपलब्धता का अर्थ यह नहीं है कि हर परिवार उसे वहन करने में सक्षम है। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब किसी मध्यमवर्गीय या कम आय वाले परिवार में कोई गंभीर बीमारी दस्तक देती है। परिवार वर्षों तक बच्चों की शिक्षा, घर, विवाह या भविष्य के लिए बचत करता है। एक गंभीर चिकित्सकीय आपातस्थिति अचानक उस बचत का बड़ा हिस्सा समाप्त कर सकती है। कुछ परिवार अस्पताल के बिल चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं, संपत्ति बेचते हैं या रिश्तेदारों पर निर्भर हो जाते हैं। कई परिस्थितियों में बीमारी आर्थिक रूप से स्थिर परिवार को भी लंबे समय तक कर्ज के बोझ में डाल सकती है। यह बोझ केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित नहीं है। कई दीर्घकालिक बीमारियों में लगातार दवाइयाँ, नियमित जांच और बार-बार चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीजों और उनके परिवारों को महीनों या वर्षों तक खर्च करना पड़ सकता है। अलग-अलग खर्च भले ही छोटे दिखाई दें, लेकिन लंबे समय में उनका कुल प्रभाव बहुत भारी हो सकता है। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है। विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को अक्सर दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता है। यात्रा, रहने, भोजन और काम से होने वाली आय के नुकसान का खर्च भी चिकित्सा खर्च में जुड़ जाता है। इस प्रकार मरीज को एक साथ दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है-इलाज का खर्च और इलाज तक पहुँचने का खर्च।

स्वास्थ्य और रोजगार के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, तो परिवार को केवल चिकित्सा खर्च ही नहीं उठाना पड़ता, बल्कि मरीज के काम न कर पाने से आय का नुकसान भी हो सकता है। कई बार परिवार के किसी अन्य सदस्य को मरीज की देखभाल के लिए अपना काम अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार बीमारी बढ़ते खर्च और घटती आय-दोनों का दोहरा आर्थिक बोझ पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य बीमा परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता और पर्याप्त कवरेज भी आवश्यक है। लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी बीमा पॉलिसी में क्या शामिल है, उसकी सीमाएँ क्या हैं और दावा करने की प्रक्रिया क्या है। साथ ही, बीमा व्यवस्था को आम लोगों के लिए सरल, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध बनाया जाना चाहिए। बीमा केवल कागज पर मौजूद सुरक्षा नहीं, बल्कि जरूरत के समय वास्तविक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला माध्यम होना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र परिवारों पर आर्थिक दबाव कम कर सकते हैं, यदि वहाँ सस्ती या निःशुल्क चिकित्सा, दवाइयाँ और जांच सुविधाएँ उपलब्ध हों। मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था से बीमारियों का शुरूआती स्तर पर पता लगाया जा सकता है, जब उनका उपचार अपेक्षाकृत सरल और कम खर्चीला हो सकता है। इसलिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना उन्नत उपचार पर दिया जाता है। रोकथाम अक्सर इलाज से कम खर्चीली होती है। नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता, स्वच्छ वातावरण और सामान्य बीमारियों के प्रति जागरूकता अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बीमारी को रोका जा सकता है, बल्कि यह इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में उपचार के साथ-साथ रोकथाम को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दवा उद्योग की भी इस दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दवाइयाँ सामान्य उपभोक्ता वस्तुएँ नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक वस्तुएँ हैं। अनुसंधान और नई दवाओं के विकास में निवेश आवश्यक है, लेकिन दवाओं की सामर्थ्य और उपलब्धता भी स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और कीमतों में पारदर्शिता मरीजों पर आर्थिक बोझ कम करने में मदद कर सकती है।

चेहरे पे चढ़ा मुखौटा

उदय कशोर साह

कविता

रे पुरवाई तेरी बात मेरे मन में समाई
मुझे भी बहा ले. चल तूँ अपने साथ
बस जाऊँगा उस शांत दुनियाँ में मैं
जहाँ पे ना हो दुश्मनी की काली रात

उब चुका है मेरी जीवन की जिन्दगानी
नफरत की जहाँ होती व्यापार दिन सात
ईष्या द्वेष की बजती है। जहाँ पे तराने
बेईमानों की होती है जहाँ पे अट्टाहास

हैवानियत जहाँ जर्रा जर्रा में व्याप्त है
कौन करे यहाँ प्रेम बुटे की कोई बात
अपनापन की हो गई जहाँ विर्सजन
हर जालिम लगाये बैठा है। करने घात

भूल गया मानवता की खेती जब
नहीं रहा गोत्र और मन में संस्कार
बम बारूद की ढेर पे सब कोई बैठा
मुखौटा चढ़ा है हर चेहरे पे मेरे यार

बहुरूपिये बन गया आस पड़ोसी भी
कहाँ से ढुँढ लाऊँ संभ्रांत सा परिवार
छल कपट की चलन है जग में जहाँ
विश्वास किस पे करूँ ओ परवरदिगार

ले जाकर बसा दो उस धरती पे हमें
भले हो मेरी पर्णकुटी की औकात
रूखी सुखी खा कर लेगें वहाँ बसर
सूकून की हो जहाँ बून्दों की बरसात

लोकतंत्र में मोब लीचिंग,भीड़ तंत्र के विवेक-हीन निर्णय का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं

संजीव ठाकुर
लेखक

सामूहिक भीड़ का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्र विवेक-बुद्धि धीरे-धीरे सामूहिक उन्माद के सामने दबने लगती है। सड़क पर खड़ी भीड़ जब किसी आरोप, अफवाह, धार्मिक पहचान, जातीय पूर्वाग्रह अथवा सोशल मीडिया पर प्रसारित अधूरी सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति समाज अथवा बड़े समूह के निर्णय को दोषी ठहराकर स्वयं दंड देने लगती है, तब वह केवल एक व्यक्ति पर हिंसा नहीं करती, बल्कि कानून के शासन, संविधान और न्याय व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती देती है। मॉब लिंचिंग इसी भीड़-मानसिकता का सबसे भयावह रूप है।

विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक' ग्रुप साइकोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ इगो' में भीड़ के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए बताया कि समूह में व्यक्ति की भावनाएं तीव्र हो सकती हैं और उसकी बौद्धिक आलोचनात्मक क्षमता कमजोर पड़ सकती है। फ्रायड ने सामूहिक मानसिकता को आदिम समूह-मानस से जोड़ते हुए यह समझाने का प्रयास किया कि भीड़ में व्यक्ति का व्यक्तिगत विवेक किस प्रकार दब सकता है।यही कारण है कि अफवाह भीड़ में तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसे बढ़ाता है, तीसरा उसमें अपनी कल्पना जोड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक झूठ सामूहिक सत्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है।मॉब लिंचिंग कानून के स्थान पर उन्माद

मॉब लिंचिंग केवल हत्या का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति या समूह स्वयं को न्यायाधीश, पुलिस और जल्लाद तीनों समझने लगता है।

लोकतांत्रिक राज्य में अपराध का निर्धारण भीड़ नहीं करती। अपराध की जांच पुलिस करती है, अभियोजन अपना पक्ष रखता है और न्यायपालिका साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है। इसलिए भीड़ द्वारा किया गया तथाकथित न्याय वास्तव में न्याय नहीं, बल्कि कानून के शासन का अपहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की गंभीरता को देखते हुए राज्यों को निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। हर भीड़ हिंसक नहीं होती। स्वतंत्रता आंदोलन के जनसमूह, किसी प्राकृतिक आपदा में सहायता करने वाले नागरिक, लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सामाजिक सुधार के लिए जुटे लोग भी भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। अंतर यह है कि ऐसी सामूहिकता नैतिक उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से संचालित होती है। समस्या तब शुरू होती है जब भीड़ व्यक्ति की विवेकशीलता को निगल लेती है और उसमें मैंने नहीं किया, सबने किया जैसी मानसिकता पैदा हो जाती है। तब जिम्मेदारी बिखर जाती है और अपराध सामूहिक हो जाता है। भीड़ में व्यक्ति अपनी पहचान खोकर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक इकाई का हिस्सा बन जाता है, जिसमें भावनाएं तर्क पर भारी पड़ सकती हैं। वह निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन भीड़ के लिए सत्य की जांच से अधिक महत्वपूर्ण उसका तत्कालिक क्रोध हो जाता है। यही कारण है कि अफवाह भीड़ में तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसे बढ़ाता है, तीसरा उसमें अपनी कल्पना जोड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक झूठ सामूहिक सत्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है। मॉब लिंचिंग में कानून के स्थान पर केवल उन्माद ही होता है।मॉब लिंचिंग केवल हत्या का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति या समूह स्वयं को न्यायाधीश, पुलिस और जल्लाद तीनों समझने लगता है।

किसी व्यक्ति पर चोरी, बच्चा चोरी, पशु हत्या, धार्मिक अपमान, सांप्रदायिक अपराध अथवा किसी अन्य अपराध का आरोप लगते ही यदि भीड़ उसे घेरकर मार डालती है, तो उस व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर ही नहीं मिलता। वह निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन भीड़ के लिए सत्य की जांच से अधिक महत्वपूर्ण उसका तत्कालिक क्रोध हो जाता है।

यहां सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं है कि भीड़ ने हत्या क्यों की प्रश्न यह भी है कि ऐसी मानसिकता पैदा क्यों हुई?

इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण एक साथ काम करते हैं।

असमानता, बेरोजगारी और कुंठा

आज का समाज उपभोक्तावादी आकांक्षाओं से संचालित है। सफलता के चमकदार प्रतीक सामने हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के अवसर सभी के लिए समान नहीं हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार न मिलना, अल्प रोजगार, आर्थिक असमानता और सामाजिक अवसरों का केंद्रीकरण युवा मन में निराशा और कुंठा पैदा कर सकता है।

भारत में संपत्ति के वितरण को लेकर विभिन्न रिपोर्टों में गंभीर असमानता सामने आती रही है। उदाहरण के लिए, ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट में शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 77.4 प्रतिशत और शीर्ष 1 प्रतिशत के पास 51.53 प्रतिशत हिस्सा बताया गया था। आंकड़ों की पद्धति और वर्ष के अनुसार अनुपात बदल सकते हैं, लेकिन व्यापक तथ्य यह है कि आर्थिक असमानता लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चुनौती है।

यह कहना उचित नहीं होगा कि गरीबी या बेरोजगारी सीधे मॉब लिंचिंग को जन्म देती है। अधिकांश गरीब और बेरोजगार लोग हिंसक नहीं होते। लेकिन जब आर्थिक निराशा के साथ सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक उकसावा, पहचान की राजनीति, अफवाह और संस्थाओं पर अविश्वास जुड़ जाते हैं, तब सामूहिक उन्माद के लिए जमीन तैयार हो सकती है।

शिक्षा में केवल डिग्री नहीं, विवेक भी होना चाहिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं होना चाहिए। यदि स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा व्यक्ति को रोजगार योग्य तो बनाती है, लेकिन उसे संवैधानिक मूल्यों, सहिष्णुता, तर्क, संवाद और असहमति का सम्मान नहीं सिखाती, तो शिक्षा अधूरी है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड़, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित कराकर ग्राउन्ड फ्लोर, दुर्गा टॉवर, आर.डी.सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया। संपादक : ललित शर्मा
सम्पर्क सूत्रः 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

आईजीआरएस प्रकरणों में डिफाल्टर व सी श्रेणी न आए: जिलाधिकारी जसजीत कौर

वेलकम इंडिया/महमूद रजा

बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आईजीआरएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस प्रकरणों में किसी भी स्तर पर डिफाल्टर श्रेणी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता से शिकायत के निस्तारण के संबंध में संतुष्टि फीडबैक लिया जाता है अतः अधिकारी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आईजीआरएस के प्रकरणों को स्वयं देखें और उनका गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करते हुए समयबद्ध एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी समस्या को समझें तथा नियमानुसार संभव समाधान कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करें। जिन प्रकरणों का निस्तारण नियमों के अनुसार संभव नहीं है, उनमें शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से कारणों से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न बरती जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण करें।बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने जिला गंगा समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने पूर्व में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की जियो-ट्रैकिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की जियो-ट्रैकिंग से उनकी स्थिति एवं संरक्षण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जियो-ट्रैकिंग कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जनता के बीच पहुंचे सपा नेता राजकुमार राजू, बोले- समस्याओं के समाधान को जारी रहेगा संघर्ष

पूरनपुर/पीलीभीत (वेलकम इंडिया)। 129-विधानसभा पूरनपुर क्षेत्र में मंगलवार को समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय नेता राजकुमार राजू ने भ्रमण कर क्षेत्र के सम्मानित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से क्षेत्र की स्थिति और विभिन्न समस्याओं को लेकर संवाद किया तथा जनसमस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए आवश्यक स्तर पर प्रयास किए जाने की बात कही।क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान राजकुमार राजू ने कहा कि जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं को लगातार सुनना और उनके समाधान के लिए आवाज उठाना ही सच्ची जनसेवा है। उन्होंने कहा कि पूरनपुर विधानसभा की जनता के सुख-दु:ख में वह हमेशा उनके साथ खड़े हैं और क्षेत्र के विकास एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाते रहेंगे।उन्होंने कहा कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर लोगों की बात सुनकर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों तक उनकी समस्याएं पहुंचाना आवश्यक है, ताकि समय रहते उनका समाधान कराया जा सके। इसी उद्देश्य से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। राजकुमार राजू ने कहा कि समाजवादी विचारधारा हमेशा आम आदमी, किसान, मजदूर, युवा और कमजोर वर्ग के हितों की बात करती रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों को भरोसा दिलाया कि जनहित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा और समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लोगों ने भी राजकुमार राजू के समक्ष अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं रखीं। उन्होंने सभी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विषयों पर आवश्यक संवाद का भरोसा दिया। राजकुमार राजू ने कहा कि क्षेत्र की जनता के सुख-दु:ख में साथ खड़ा रहना और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास करना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वह इसी भावना के साथ पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे।

हापुड़ तक इलेक्ट्रिक बस सेवा के विस्तार की मांग, परिवहन मंत्री को सौंपा प्रार्थना पत्र

हापुड़/लखनऊ (वेलकम इंडिया)। हापुड़ जनपद के हजारों दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं नौकरीपेशा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरठ-गाजियाबाद से संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार हापुड़ शहर तक किए जाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में लखनऊ स्थित आवास पर माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से आत्मीय भेंट कर उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की गई कि मेरठझगाजियाबाद से संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा को हापुड़ तक विस्तारित किया जाए। इससे हापुड़ के लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री से जनहित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। इलेक्ट्रिक बस सेवा के हापुड़ तक विस्तार से जिले के लोगों को मेरठ और गाजियाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में आवागमन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।

धनपति वर्मा ने गांव-गांव पहुंचकर साधा जनसंपर्क

वेलकम इंडिया संवाददाता

बरखेड़ा/पीलीभीत। बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता धनपति वर्मा ने 128 विधानसभा बरखेड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यापक जनसंपर्क एवं भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने नवदिया घीसी, बंजरिया, दियूरी, दियूरी गौटिया, महुआ, रामनगरिया, अजीतपुर, पटपरापुर, जमुनिया, पुरवा, खाग, मानपुर हटुआ, सराय सुंदर, कैंच और तकिया सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान जगह-जगह ग्रामीणों और पार्टी कार्यकताओं ने उनका स्वागत किया।

जनसंपर्क के दौरान धनपति वर्मा ने ग्रामीणों से सीधे मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, किसानों की समस्याओं तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी परेशानियां उनके सामने रखीं। धनपति वर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई लगातार आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग परेशान है। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर सरकार का ध्यान अपेक्षित रूप से नहीं है। सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाती रही है। पार्टी की नीतियों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान, अधिकार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों का जवाब देगी। धनपति वर्मा ने कार्यकताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकताओं की एकजुटता बेहद जरूरी है। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों और पार्टी कार्यकताओं में उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने धनपति वर्मा का स्वागत करते हुए क्षेत्र में जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

ग्राम अटूटा में दो भाइयों से मारपीट, चार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वेलकम इंडिया/राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

हापुड़। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने ग्राम अटूटा निवासी दो भाइयों हर्ष और निखिल के साथ मारपीट करने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन पुत्र सुखबीर, अंशुल पुत्र मोनू, आकाश पुत्र सुनील तथा गौरव पुत्र सुरेश, निवासी ग्राम उपैडा, थाना बाबूगढ़, जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर ग्राम अटूटा निवासी हर्ष व निखिल के साथ मारपीट करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।

सावन महोत्सव 'उत्कर्ष' में छात्राओं ने बिखेरा रंग

लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों पर प्रबंधक ने किया सम्मानित

वेलकम इंडिया/संदीप तिवारी

मिजार्मुराद/कछवारोड़। गौर गांव (मिजार्मुराद) स्थित स्व. वंशनारायण सिंह महिला महाविद्यालय में मंगलवार को सावन महोत्सव 'उत्कर्ष' का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को सावनमय कर दिया। कार्यक्रम की शुरूआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। लोकगीत में रोशनी और आंचल पटेल की प्रस्तुति को खूब सराहा गया। वहीं समूह नृत्य में सौम्या, माही, आंचल, किरण, पिंकी वर्मा और रितु यादव ने अपनी कला से दर्शकों का मन मोह लिया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक एवं भाजपा नेता संजीव सिंह गौतम ने उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रबंधक संजीव सिंह गौतम ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमारी लोक संस्कृति को जीवित रखने में मदद करते हैं। उन्होंने छात्राओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्रचार्या डॉ. संगीता सिंह, सचिव योगेश सिंह, डॉ. आशुतोष उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी 'सुमित', डॉ. अंजना सिंह, अंजली जायसवाल, डॉ. विजय सिंह, श्वेता कुमारी, अमृता सिंह, स्नेहा मिश्रा, संजू गुप्ता, मुकेश यादव, राजेश सिंह, रामजी यादव, वीरेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य प्रवक्तागण और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

खेतों का कटान कर गलखा देवी मंदिर की ओर बढ़ी गंगा की धार

वेलकम इंडिया/महमूद रजा

बिजनौर मंडावर। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर बह रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार वर्षा से गंगा की मुख्य धारा ने दिशा बदल ली है और अब वह खेतों की ओर मुड़ गई है।तेज धारा खेतों का कटान करती हुई गलखा देवी मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि नदी का यह रुख मंदिर और आसपास के खेतों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है।कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग द्वारा गंगा में लकड़ी की बल्लियाँ गाड़कर उनमें रेत भरे बोरे डाले जा रहे हैं, ताकि पानी की तेज धार को नियंत्रित किया जा सके और कटान की रफ्तार धीमी हो। ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। वे विभाग से और प्रभावी उपाय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि मंदिर और खेतों को नदी के प्रकोप से बचाया जा सके।

अमरिया में कृषि भूमि पर कब्जे का आरोप, पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर उठ रहे सवाल

वेलकम इंडिया संवाददाता

अमरिया/पीलीभीत। अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम हेतमडाड़ी में कृषि भूमि पर कथित अवैध कब्जे और पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर मामला सामने आया है। सितारगंज निवासी सर्वजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उसकी कृषि भूमि पर बिना सहमति के कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि लंबे समय से वह अपनी भूमि की सुरक्षा और न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।सर्वजीत सिंह के अनुसार, अन्य जिले से आए कुछ लोगों ने क्षेत्र में प्रभाव कायम करते हुए पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए उसकी कृषि भूमि पर कथित रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि भूमि पर उसकी सहमति के बिना निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इससे उसे आर्थिक नुकसान के साथ ही अपनी जमीन को लेकर भविष्य की चिंता भी सताने लगी है।पीड़ित ने बताया कि उसने मामले की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराने के साथ ही संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराया है। इसके बावजूद अभी तक उसे अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी है। उसका आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते शिकायत पर कार्रवाई में देरी हो रही है।सर्वजीत सिंह ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों की जांच के साथ मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जाए। यदि जांच में अवैध कब्जा या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए।पीड़ित का कहना है कि वह अपनी जमीन और न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है। उसने जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

बिजनौर में 13 माह की अनजान मासूम बच्ची के लिए फरिश्ता बने जलालाबाद के पत्रकार कामिल अंसारी रक्तदान कर बचाई जान

वेलकम इंडिया/महमूद रजा

बिजनौर। नजीबाबाद कस्बा जलालाबाद के मोहल्ला काजियान निवासी पत्रकार कामिल अंसारी ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बिजनौर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती 13 माह की मासूम बच्ची फातिमा को गंभीर एनीमिया होने के कारण 250 ML B Positive (B+) फ्रेश ब्लड की सख्त जरूरत थी। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक द्वारा जारी ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म पर डॉक्टर ने तुरंत खून की व्यवस्था करने को कहा था। जैसे ही इसकी सूचना पत्रकार कामिल अंसारी को मिली, वह तुरंत संजीवनी चैरिटेबल ब्लड सेंटर नजीबाबाद पहुंचे और बच्ची के लिए रक्तदान किया। कामिल अंसारी ने कहा कि ₹रक्तदान महादान है, मेरे थोड़े से खून से अगर किसी मासूम की जान बचती है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं।बच्ची के परिजनों ने कामिल अंसारी का आभार जताया है।

तिथि भोजन में उत्साह से झूमे चंदिया हजारा के बच्चे

गुणवत्ता जांचने को अधिकारियों ने चखा विद्यालय का भोजन

वेलकम इंडिया संवाददाता

पूरनपुर/पीलीभीत। प्राथमिक विद्यालय चंदिया हजारा में मंगलवार को तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में बच्चों को विशेष भोजन कराया गया और अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भोजन की गुणवत्ता को परखा। तिथि भोजन पाकर विद्यालय के बच्चों में खासा उत्साह नजर आया।कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम प्रशासक वासुदेव कुंडू, पुलिस चौकी इंचार्ज ऋषिपाल गिरी, राजस्व निरीक्षक अदनान राशिद, क्षेत्रीय लेखपाल नीरज कुमार तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेमानंद मौजूद रहे। अतिथियों की मौजूदगी में बच्चों को भोजन परोसा गया। इस दौरान बच्चों को पूरी-सब्जी के साथ स्वादिष्ट खीर भी दी गई। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भोजन किया।कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों ने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विद्यालय में भोजन तैयार करने से लेकर बच्चों को परोसने तक की व्यवस्था को देखा गया। अधिकारियों ने भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

बताया गया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में समय-समय पर तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना तथा भोजन की व्यवस्था की नियमित निगरानी करना है। कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो।तिथि भोजन के दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। विशेष भोजन मिलने से बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। मौजूद अधिकारियों ने भी बच्चों से भोजन के संबंध में जानकारी ली और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों ने तिथि भोजन कार्यक्रम को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलने के साथ ही मिड-डे मील की गुणवत्ता पर भी लगातार नजर बनी रहती है। अधिकारियों ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही।

कन्नौर और बीरमपुर में नैना गुर्जर का जनसंपर्क, सपा की नीतियों पर की चर्चा

वेलकम इंडिया/राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

गढ़मुक्तेश्वर। समाजवादी पार्टी की नेत्री नैना गुर्जर ने कन्नौर और बीरमपुर क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और जनता की अपेक्षाओं को लेकर चर्चा की तथा लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।नैना गुर्जर ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों की आवाज को मजबूती से उठाती रही है। उन्होंने कार्यकताओं से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया।नैना गुर्जर की क्षेत्र में लगातार सक्रियता से सपा कार्यकताओं में उत्साह नजर आया। इससे पहले भी वह गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से अपनी सक्रियता दर्ज करा चुकी हैं।

वर्दी में सेवा, हाथों में झाड़ू: सावन के चौथे सोमवार के बाद पुलिस ने मंदिर-तालाबों में चलाया स्वच्छता अभियान

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। सावन के चौथे सोमवार के बाद मंगलवार को संतकबीरनगर पुलिस ने जनसेवा और सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए जनपदभर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित मंदिरों, मंदिर परिसरों और आसपास के तालाबों की साफ-सफाई कराई गई। अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने स्वयं हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की और कूड़ा-कचरा हटाकर धार्मिक स्थलों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह और संबंधित क्षेत्राधिकारियों के पर्यवेक्षण में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाया। मंदिर परिसरों के साथ-साथ आसपास के तालाबों और सार्वजनिक स्थानों पर भी विशेष रूप से सफाई की गई। स्वच्छता अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने मंदिर और तालाब परिसरों में श्रमदान किया। उन्होंने आसपास बिखरे कूड़े-कचरे को हटाया और गंदगी वाले स्थानों की सफाई की। इस दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फैलाने की अपील की गई। पुलिसकर्मियों ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की गई कि वे कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और मंदिरों तथा सार्वजनिक परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें।

संतकबीरनगर पुलिस की इस पहल ने पुलिस की जनसेवा की भूमिका को भी सामने रखा। अभियान के माध्यम से संदेश दिया गया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों, जनहित और जनजागरूकता के कार्यों में सहभागिता भी उसकी जिम्मेदारी है। पुलिसकर्मियों को स्वयं सफाई करते देखकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने अभियान की सराहना की। इससे पुलिस और आमजन के बीच सकारात्मक संवाद तथा विश्वास को और मजबूती मिली। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान से मंदिरों और तालाब परिसरों में स्वच्छ एवं सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। सावन के चौथे सोमवार के बाद चलाया गया यह अभियान स्वच्छता, सेवा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के साथ-साथ पुलिस की संवेदनशील और जनसरोकारों से जुड़ी भूमिका को भी दर्शाता है।

श्रीनगर में उत्तराखंड संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत सप्ताह हुआ का शुभारंभ, निकाली गई विशाल संस्कृत शोभायात्रा

वेलकम इंडिया संवाददाता

देहरादून। आज श्रीनगर में उत्तराखंड संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत सप्ताह का शुभारंभ विशाल संस्कृत शोभायात्रा निकाल कर किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉ. रावत ने इस अवसर पर कहा कि संस्कृत हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, ज्ञान, परंपरा एवं संस्कारों की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत सप्ताह के माध्यम से युवा पीढ़ी को देववाणी संस्कृत से जोड़ने तथा इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समाज को प्रेरित करने का यह प्रयास सराहनीय है।

पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा जुलहेंदी गांव

अमृतसर सरोवर खुदाई के लिए 19.90 लाख रुपये की पहली किस्त जारी...

वेलकम इंडिया संवाददाता

मथुरा/गोवर्धन। मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जुलहेंदी में वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर खुदाई के लिए अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ भूमि पूजन कर नींव रखी। सरोवर निर्माण के लिए 19.90 लाख रुपये की पहली किस्त स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही खुदाई और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अमृतसरोवर के आसपास पौराणिक वन क्षेत्र भी विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है। मंगलवार को आर ई डब्लूयु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अजय सक्सेना जुलहेंदी पहुंचे। यहां कौन्हई मार्ग स्थित चित्र गुप्त पीठ के सामने अमृत सरोवर के लिए स्वामी सच्चिदानंद महाराज, उत्तरप्रदेश पर्यावरण समिति के सदस्य मनोज सक्सेना के साथ भूमि पूजन एवं नींव रखकर उद्घाटन किया। अजय सक्सेना ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने वीबीजी राम जी योजना संचालित की है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को खुशहाल बनाने के लिए अमृतसरोवर और वन क्षेत्र विकसित करने का काम किए जा रहे।

मृतसरोवर के बनने से यहां जल संचय होगा और वन क्षेत्र विकसित होने से पर्यावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण समिति के सदस्य मनोज सक्सेना ने बताया कि सरोवर के आस पास वन क्षेत्र में बैठने के लिए आधुनिक बेंच लगवाई जाएंगी और बाउंड्री बॉल पर राधाकृष्ण की लीलाओं की आकृतियां उकेरी जाएंगी। पंचायत सचिव हरेंद्र सिंह ने बताया अमृतसरोवर के लिए पहली किस्त के रूप में 1990478 रुपये स्वीकृत हुए हैं। भूमि पूजन के साथ कार्य शुरू कराया गया है। इस अवसर पर इंजीनियर दिनेश शर्मा, हरीशचंद्र दीक्षित, भूपेंद्र सिंह, सिविल इंजीनियर शिल्पा, पूर्व प्रधान यादवीर, आयुष, सुरेशा नंद महाराज आदि उपस्थित थे।

प्रधानाचार्यों ने सीखे वित्तीय प्रबंधन और विद्यालय संचालन के गुर

डायट खलीलाबाद में तीन दिवसीय प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन, विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता पर हुई चर्चा

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), खलीलाबाद में दक्ष मॉड्यूल पर आधारित तीन दिवसीय प्रधानाचार्य प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हुआ। प्रशिक्षण में जनपद के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान प्रधानाचार्यों को विद्यालय संचालन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, स्टाफ प्रबंधन, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण की अध्यक्षता उप शिक्षा निदेशक डॉ. सबीहा मुमताज ने की, जबकि संचालन संतोष कुमार ने किया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने प्रधानाचार्यों को विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए आवश्यक प्रबंधन से जुड़े शासन के नवीनतम प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कौशल से अवगत कराया। कार्यशाला के अंतिम दिन प्रधानाचार्यों को विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों से अवगत कराया गया। विद्यालय के आय-व्यय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को व्यवस्थित एवं नियमानुसार बनाए रखने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही वित्तीय निदेशों और उनके अनुपालन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और अभिलेखों का सही रखरखाव बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्यों को निदेशों के अनुरूप विद्यालय के वित्तीय कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन और स्टाफ से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। प्रधानाचार्यों को बताया गया कि विद्यालय में बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ प्रभावी समन्वय आवश्यक है। इसके अलावा कार्य के दौरान आने वाले दबाव और चुनौतियों के बीच भी बेहतर निर्णय लेने तथा जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के साथ विद्यार्थियों, अभिभावकों और समाज के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रधानाचार्य संजय द्विवेदी ने प्रशिक्षण के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं के लिए डायट के समस्त स्टाफ के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के बदलते परिवेश और नई चुनौतियों को देखते हुए प्रधानाचार्यों के लिए इस तरह के नवाचार आधारित प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। इससे विद्यालयों के संचालन में नई कार्यप्रणाली और बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।

प्रशिक्षण में निशा यादव, संजय द्विवेदी, हरिनंदन यादव, अरुण ओझा, राकेश चौधरी, मुजीबुल्लाह, यूनुस अख्तर, रविंद्र चौरसिया, अभिमन्यु सिंह, विनोद उपाध्याय, सुमन त्रिपाठी, विट्टन विश्वकर्मा, विनोद चौरसिया, ओम प्रकाश सिंह, शैलेंद्र शुक्ला, कौशलेंद्र सिंह, प्रदीप मिश्र, सत्यम सिंह, यशकांत यादव, कमलेश कुमार, श्रवण कुमार, सतीश भारती, राजदेव तिवारी, भरत सिंह, नरेंद्र पटेल, संतलाल, भूपेंद्र कुमार, विजेंद्र, अवध राज, निमिषा, नाजिया, अनामिका, सुरेश बिंद समेत बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य मौजूद रहे।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतो में इजाफा आम आदमी के हितों पर कुठाराघात है: शान्ति देवी

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। देश का हर वर्ग भाजपा सरकार से नाराज है। चीनी के दामों में हुई वृद्धि से आम आदमी आक्रोशित है। रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है मिठाई के दाम आसमान छूने लगे हैं। सरकार का आम आदमी के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उक्त बातें महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष शान्ति देवी ने वेलकम इंडिया से खास बातचीत में कहीं।

उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतो में इजाफा आम आदमी के हितों पर कुठाराघात है। बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। जननायक राहुल गाँधी निरंतर देश के आम आदमी के हितों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्रों की गूँज के माध्यम से छात्रों की समस्याओ को उठा रहे हैं। किसानों, व्यापारियों, मोची, कुलियो से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। देश व प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहते हैं।

लाइव डिबेट में अभद्रता का आरोप, मुकदमा नहीं हुआ तो आमरण अनशन

वेलकम इंडिया संवाददाता

मथुरा। डी.डी. न्यूज की लाइव टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर अभद्र, आपत्तिजनक और धमकीपूर्ण भाषा के इस्तेमाल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद ने थाना सदर बाजार में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने और डिबेट की मूल रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित कराने की मांग की है। निषाद का आरोप है कि डिबेट के दौरान उनकी मां को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि ऐसी महिला को अपमानित करना है, जिसका राजनीति या बहस से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे और संविधान व कानून के रास्ते पर चलेंगे। कुंवर सिंह निषाद ने चेतावनी दी है कि यदि 26 अगस्त तक मुकदमा दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो वह उसी समय से आमरण अनशन पर बैठेंगे। मामले में कांग्रेस विधि विभाग की ओर से लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी शिकायत दिए जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग ने ऐसे टीवी डिबेट कार्यक्रमों में पार्टी प्रवक्ताओं को महंत राजू दास के साथ शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है।

निषाद ने पुलिस से डी.डी. न्यूज की मूल लाइव रिकॉर्डिंग, ऑडियो-वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को सुरक्षित कर निष्पक्ष जांच में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक बहस में वैचारिक मतभेद और तीखी राजनीतिक आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन व्यक्तिगत गाली-गलौज, परिवार को निशाना बनाना और कथित धमकीपूर्ण भाषा स्वीकार्य नहीं है।

साइबर ठगी के पीड़ितों को 1.36 लाख रुपये वापस

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात साइबर ठगी पीड़ितों की 1,36,476.53 रुपये की धनराशि वापस कराई। साइबर सेल प्रभारी जयप्रकाश दूबे और अपराध निरीक्षक वीरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने संबंधित बैंकों से समन्वय कर धनराशि वापस कराई। ठगी के मामलों में पार्सल भेजने, पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने, विदेश में नौकरी दिलाने, ऑनलाइन खरीदारी, खाते में रुपये ट्रांसफर कराने और एलआईसी किस्त जमा कराने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों की शिकायत पर साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा ने संबंधित बैंक एवं अन्य माध्यमों से प्रभावी पैरवी की। कार्रवाई के बाद पीड़ितों के खातों में धनराशि वापस कराई गई। पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या गोपनीय विवरण साझा न करने की अपील की है।

नववर्ष मेला समिति रक्तदान शिविर आज

मथुरा (वेलकम इंडिया)। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में नववर्ष मेला समिति मथुरा के तत्वावधान में सदभावना चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर सरस्वती शिशु मन्दिर दीनदयाल नगर मथुरा में कल (आज) प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। यह जानकारी समिति महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव ने दी है। मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा ने बताया है कि यह रक्तदान शिविर समिति के सेवा कार्यों के अंतर्गत हो रहा है। रक्तदान दाताओं के लिए उपहार, जलपान, प्रमाण-पत्र और वालन्टियर कार्ड भी दिया जायेगा।

भागवत आचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री का नागरिक अभिनंदन

वेलकम इंडिया संवाददाता

मथुरा/वृंदावन। अंतरराष्ट्रीय भागवत आचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री द्वारा श्रीनाथ वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करने के साथ उनके सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए भगवान श्री परशुराम शोभायात्रा समिति रजि मथुरा एवं ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति रजि उत्तर प्रदेश द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट करने के साथ दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। भगवान परशुराम शोभायात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित रामगोपाल शर्मा ने कहा कि डॉ. मनोज मोहन शास्त्री अपनी कथा के माध्यम से देश-विदेश में ब्रज की महिमा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। साथ ही ब्रज में आयोजित होने वाले धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। समिति के संस्थापक अध्यक्ष विनोद दीक्षित ने कहा कि डॉ. मनोज मोहन शास्त्री उनकी टीम के प्रदेश संरक्षक होने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वह समय-समय पर समाजसेवा के कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। उनके इसी सेवा भाव को देखते हुए समाज की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री बंसीलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ब्रज की धरोहर हैं। उन्होंने हमेशा ब्रज की संस्कृति, धर्म और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किया है। सम्मान से अभिभूत डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ने सभी का आभार व्यक्त किया और उपस्थित लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में संजय हरियाणा, हरीश शर्मा, ललित पंडित, अजय शर्मा, के.के. शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

3446 प्राविधिक सहायकों को मिले नियुक्ति पत्र, संतकबीरनगर में 36 अभ्यर्थियों की हुई नियुक्ति

लखनऊ में किया नियुक्ति पत्र वितरण; जिलाधिकारी ने नवचयनित प्राविधिक सहायकों से किसानों के हित में पूरी निष्ठा से काम करने की कही बात

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 3446 प्राविधिक सहायकों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण संतकबीरनगर के कलेक्ट्रेट सभागार में भी किया गया, जिसे जिलाधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नवचयनित प्राविधिक सहायकों ने देखा और सुना। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के पद पर चयनित 36 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी आलोक कुमार ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर एमएलसी प्रतिनिधि अमरीश राय और मुख्य विकास अधिकारी जयेकश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। नवचयनित प्राविधिक सहायकों को शुभकामनाएं देते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने कहा कि कृषि विभाग किसानों के उत्थान, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू करता है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राविधिक सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का नियमित रूप से निर्वहन करते हुए पूरे मनोयोग और निष्ठा के साथ किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए विभागीय कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है।

उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ की ओर से 23 जून 2026 को 3446 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया था। शासन के निदेशों के क्रम में संतकबीरनगर जनपद में कृषि विभाग के लिए कुल 36 प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर विभागीय जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राविधिक सहायक किसानों और विभाग के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे तथा कृषि योजनाओं को गांव और खेत तक पहुंचाने में भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने सभी नवचयनित प्राविधिक सहायकों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। साथ ही उनसे किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समझने और शासन की योजनाओं का पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी डॉ. सर्वेश कुमार यादव समेत कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और सभी नवचयनित प्राविधिक सहायक मौजूद रहे।

साहब जल्दी बना दो काफलीगैर में डिग्री कॉलेज

नेताओं ने पहले विधायक और बाद में जिलाधिकारी को सौपा ज्ञापन

वेलकम इंडिया संवाददाता

बागेश्वर। जल्द आगामी चुनाव से पहले काफलीगैर तहसील क्षेत्र में डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज नही बनाए जाने परअब क्षेत्रवासियों ने गहरी नाराजगी जताई है।वही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं ने जल्द क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग को लेकर पहले क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास से मुलाकात की।और जल्द काफलीगैर में डिग्री कॉलेज खोले जाने की मांग की।वही शिष्टमण्डल में क्षेत्रीय नेताओं और डिग्री कालेज खोलो संघर्ष समिति के प्रमुख ठाकुर सिंह,ज्येष्ठ प्रमुख मनीष कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष घनश्याम राणा, भाजपा नेता और पूर्व जिपं सदस्य रवि करायत, सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर विधायक से शीघ्र डिग्री कॉलेज का शासनादेश जारी कराने, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कॉलेज भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी अब तक डिग्री कॉलेज नही खुल पाने से लोगों में नाराजगी होने की बात कही गई। साथ ही जल्द मुख्यमंत्री से कॉलेज भवन के निर्माण कराए जाने की मांग की। जिस पर विधायक ने जल्द क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया।और कॉलेज खोलने हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु लगातार कार्य होने की बात कही।जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि यदि पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सात सितंबर तक सरकार द्वारा कॉलेज भवन निर्माण का शासनादेश जारी नही किए जाने पर पुनः आंदोलन करने की चेतावनी दी। वही पूर्व में घोषणा होने के बाद भी अब तक डिग्री कॉलेज का निर्माण शुरू नही होने से भाजपा नेताओं में भी असहज की स्थिति बनी हुई है। लगातार बैठकों में जनप्रतिनिधियों से मांग उठाने के बाद भी कोई सुध नही लिए जाने से विरोध के स्वर उठने के बाद भाजपा नेता जनता को दिलासा, दे रहे है। आलम ये है कि कार्यकर्ता भी उपेक्षित महसूस करने लगे हैं।

लगातार भाजपा नेता बैठकों और मंत्रियो और मुख्यमंत्री के दौरे में काफलीगैर में डिग्री कॉलेज खोले जाने की मांग कर चुके हैं।वही शिष्टमंडल ने बाद में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जल्द काफलीगैर में प्रस्तावित महाविद्यालय की स्थापना हेतु शासनादेश जारी करने की मांग की। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने आश्वस्त करते हुए बताया कि डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर जिला प्रशासन लगातार आवश्यक मानकों को पूरा कर शीघ्र कॉलेज भवन निर्माण कराने को लेकर युद्धस्तर पर शासन से पत्राचार कर रहा है। उन्होंने जल्द डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण हेतु शासन से जीओ जारी होने की बात कही। वही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्रवासी लम्बे समय से डिग्री कॉलेज खुलने की राह देख रहे हैं पर अब तक डिग्री कॉलेज का संचालन नही होने से लोगों में रोष है.उन्होंने सात सितंबर तक शासनादेश जारी नही होने पर काफलीगैर इंटर कॉलेज मोड़ के पास यात्री शेड में धरना-प्रदर्शन करने के की चेतावनी दी। इस दौरान संघर्ष समिति अध्यक्ष ठाकुर सिंह रौतेला, नवीन चंद्र जोशी, क्षेपं सदस्य गोपाल दत्त भट्ट, सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे।

राखी की डोर के साथ सुरक्षा का कवचः महिला कांस्टेबलों ने भाइयों को बांटे हेलमेट, दिलाया सड़क सुरक्षा का संकल्प

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। आगामी रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बेहद सराहनीय और अनूठी पहल देखने को मिली। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एक विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला पुलिस कांस्टेबलों ने उपस्थित जनसामान्य को अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर रक्षासूत्र बांधा और जीवन की सुरक्षा का संकल्प दिलाया।

महिला कांस्टेबलों ने भाइयों से अपील की कि वे दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा भारतीय मानक संस्थान मार्क वाला हेलमेट पहनें और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। इसके साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, निर्धारित गति सीमा में रहने और नशे की हालत में कभी भी वाहन न चलाने की शपथ दिलाई गई। इस खास मौके पर महिला कांस्टेबलों ने उपस्थित लोगों को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने भावुक संदेश देते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर राखी की डोर केवल कलाई की सुरक्षा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भाइयों के सुरक्षित घर लौटने का संकल्प भी है। इस अभियान के जरिए एआरटीओ प्रशासन ने आम जनता से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग की अपील की।

कृषि विभाग कार्यक्रम, एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने बांटे नियुक्ति पत्र

वेलकम इंडिया/मोहसिन रहमानी

कांधला। थाना क्षेत्र के गांव पंजोखरा स्थित खादी ग्रामोद्योग परिसर में कृषि विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लाइव संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसे कर्मचारियों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सुना।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता तथा एमएलसी वीरेंद्र सिंह रहे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से विकास कार्यों को लगातार गति मिल रही है। प्रदेश में सड़कों, शिक्षा, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से काम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर नई नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नियुक्ति पत्र मिलने पर कर्मचारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में कृषि विभाग सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कृषि विभाग में 84 प्राविधिक सहायकों को मिला नियुक्ति पत्र, डीएम ने दी बधाई

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक समूह-ग के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मंगलवार को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण अम्बेडकर सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की मौजूदगी में देखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने भाजपा जिलाध्यक्ष का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले के 84 नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जबकि मुख्यमंत्री प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर को आकांक्षी जिले से अग्रणी जिले में शामिल कराने में नवनियुक्त कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने काला नमक चावल की बढ़ती पैदावार और जिले में मखाना की खेती को बढ़ावा दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें, जिससे जिले का विकास हो। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सिद्धार्थनगर में अपार संभावनाएं हैं। काला नमक चावल जिले के एक जनपद, एक उत्पाद में चयनित है। सभी नवनियुक्त प्राविधिक सहायक टीम भावना के साथ कार्य करते हुए किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। इस अवसर पर सांसद डुमरियागंज के प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने भी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई दी। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मौर्या, जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उपकृषि निदेशक राजेश कुमार ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष शुक्ला, कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी समेत अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।

अतिक्रमण और जलभराव से लोग परेशान, भाकियू ने उठाई आवाज

वेलकम इंडिया/मोहसिन रहमानी

कांधला। नगर के रेलवे मार्ग पर अतिक्रमण और जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के निस्तारण की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के कार्यकताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर उच्च अधिकारियों से शिकायत की है।मंगलवार को भाकियू टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष विकास चौहान और सोशल मीडिया प्रभारी रईस पठान ने बताया कि रेलवे मार्ग पर अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया है। वहीं जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मार्ग पर पानी जमा रहता है, जिससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार पालिका प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर अतिक्रमण हटवाने और जलभराव की समस्या का शीघ्र निस्तारण कराने की मांग की है।

रक्षाबंधन से पहले मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, 77 किलो मिठाई सीज और 95 किलो को किया नष्ट

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। आगामी रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष छापामार अभियान चलाया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर के निर्देश पर सहायक आयुक्त खाद्य-द्वितीय के निर्देशन में टीम ने विभिन्न बाजारों में जांच की।अभियान के दौरान लोटन बाजार, नौगढ़ से बर्फी का एक नमूना लिया गया। वहीं खीरा मंडी चौराहा, डुमरियागंज से पेड़ा, बर्फी और मिल्क केक के नमूने संग्रहित किए गए। जांच के दौरान 77 किलोग्राम पेड़ा, बर्फी और मिल्क केक मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सीज किए गए। इसके अलावा 95 किलोग्राम पेड़ा, बर्फी और कलाकंद नष्ट कराया गया। कोनकटी चौराहा, डुमरियागंज से बालूशाही और बूंदी के लड्डू के नमूने भी लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने के लिए जागरूक किया। अभियान में सहायक आयुक्त खाद्य आरएल यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हीरा लाल, नीरज कुमार चौधरी और रंजन कुमार श्रीवास्तव शामिल रहे।

कपिलवस्तु विधानसभा में छह ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी, 11.10 करोड़ होंगे खर्च

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। विधानसभा क्षेत्र कपिलवस्तु में ग्रामीण सड़कों के विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के तहत छह मार्गों के नव निर्माण को मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण पर कुल 11 करोड़ 10 लाख 55 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। स्वीकृति मिलने से क्षेत्र के ग्रामीणों में आवागमन सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद जगी है। कपिलवस्तु विधायक श्यामधनी राही ने बताया कि स्वीकृत कार्यों में सिकरी बखरिया से लोधडीह संपर्क मार्ग, उसका-सोहास मार्ग के किमी तीन से भलुहा संपर्क मार्ग, मोहाना-लोटन मार्ग के किमी दो से रोहूडिला होते हुए रघुनाथपुर संपर्क मार्ग शामिल हैं।इसके अलावा बर्डपुर-पिपरहवा मार्ग के किमी पांच से रामभारी होते हुए नोनहवा संपर्क मार्ग, मोहनिया पूरब व पश्चिम संपर्क मार्ग तथा गोरखपुरिया डीह से अलीगढ़वा होते हुए सेमेनार संपर्क मार्ग का भी निर्माण कराया जाएगा।विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन मार्गों के निर्माण से गांवों की मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति क्षेत्र की जनता की ओर से आभार जताया। विधायक ने कहा कि सड़क, बिजली, शिक्षा समेत बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयास जारी रहेंगे।

त्योहारों पर पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन से रखी चप्पे-चप्पे पर नजर

वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

बिस्कोहर/सिद्धार्थनगर। आगामी प्रमुख त्योहारों–रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और 12 वफात–को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार शाम को साढ़े पांच बजे प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर हरे कृष्ण उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कस्बा बिस्कोहर में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर अपनी ताकत का अहसास कराया।यह फ्लैग मार्च स्थानीय पुलिस चौकी बिस्कोहर से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न संवेदनशील और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरा। पुलिस बल ने चौकी से प्रस्थान कर पश्चिम मोहल्ला, कसेरा और शाह मोहल्ला होते हुए मुख्य मार्केट का रुख किया। इसके बाद टीम पुराना डाकखाना मार्ग से होते हुए परशुराम तिराहा पहुँची और वापस पुलिस चौकी पर आकर मार्च का शांतिपूर्ण समापन हुआ। मार्च के दौरान पुलिस जवानों ने मुख्य चौराहों, संवेदनशील स्थानों और स्थानीय बाजारों में गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बीच अधिकारियों ने क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों और आम जनता से संवाद स्थापित कर सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाने की अपील की।सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह अभेद्य और चाक-चौबंद बनाने के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया। फ्लैग मार्च के दौरान कस्बे की हर गतिविधि पर बारीक नजर रखने के लिए आसमान में ड्रोन कैमरे उड़ाए गए। ड्रोन के जरिए घने मोहल्लों, मकानों की छतों और तंग गलियों की सघन निगरानी की गई, ताकि कोई भी शरारती या असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सके।प्रभारी निरीक्षक हरे कृष्ण उपाध्याय ने सख्त लहजे में हिदायत दी कि त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले या सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ पोस्ट डालने वाले उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस सुरक्षा मार्च में उपनिरीक्षक तालीमुद्दीन खान, इशांशु श्रीवास्तव, विजय कुमार, इंद्रजीत सिंह, अमरेश पांडेय, आशीष मौर्य, अजय यादव और बलराम सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे।

घर में घुसकर महिला से मारपीट का आरोप, तमंचे से धमकी देने की शिकायत

वेलकम इंडिया संवाददाता

कांधला। थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीदौलत निवासी एक व्यक्ति ने पड़ोस के दो युवकों पर घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने तथा तमंचे से जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र के गांव गढ़ीदौलत निवासी संजय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि विगत 20 अगस्त की रात करीब नौ बजे उसके पड़ोसी मोनू और सोनू उसके घर पर आए। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पत्नी शीतल के साथ लात-घूंसों और डंडों से मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार, इस दौरान मोनू ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी।पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि घटना के बाद वह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली, गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन

वेलकम इंडिया संवाददाता

बागेश्वर। पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। नाराज कार्यकताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि दमनकारी नीतियों से आंदोलनकारियों की आवाज नहीं दबाई जा सकती। यूथ कांग्रेस ऐसी नीतियों का कड़ा विरोध करेगी। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार के नेतृत्व में कार्यकर्ता मंगलवार को स्टेशन रोड स्थित गांधी मूर्ति के पास एकत्र हुए। यहां से एसबीआई तिराहे तक आक्रोश रैली निकाली और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया।

यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज और पैलेट गन से हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे दमनकारी नीति बताया। कहा कि ऐसी कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कमलेश गढ़िया, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवत सिंह डसीला, राजेंद्र टंगड़िया,किशन कठायत, जिला पंचायत सदस्य बलवंत राम, राहुल कुमार, प्रेम दानू,ईश्वर पांडे, नीरज नवीन, उम्मेद सिंह गाड़िया दीपा, खुशी, प्रेमा,और संजय चनयाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

घर में घुसकर महिला से मारपीट, आभूषण ले जाने का आरोप

कांधला। थाना क्षेत्र के मोहल्ला इदरीश बैग बिहार कॉलोनी निवासी महिला ने अपनी पुत्रवधू के मायके पक्ष के लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और सोने-चांदी के आभूषण ले जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कई लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के मोहल्ला इदरीश बैग बिहार निवासी महिला साजिदा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका अपनी पुत्रवधू के साथ किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद के बाद पुत्रवधू ने अपने मायके पक्ष के लोगों को घर पर बुला लिया। इसके बाद करीब आधा दर्जन लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया।महिला के अनुसार, शोर-शराबा होने पर आसपास के लोगों के आने की आहट सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता का आरोप है कि पुत्रवधू अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ मिलकर घर से सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई।

युवक के साथ मारपीट कर वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल

वेलकम इंडिया/मोहसिन रहमानी

कांधला। थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान निवासी युवक ने कुछ लोगों पर रास्ते में रोककर खेत में ले जाने और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और बैल्ट से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान निवासी बिलाल ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता है। आरोप है कि विगत 15 अगस्त को दोपहर करीब तीन बजे वह गांव के रास्ते से जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपी उसे खेत में ले गए और लाठी-डंडों और बैल्टों से मारपीट की। मारपीट में उसे चोटें आईं। पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था।और उक्त वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल कर दिया है। मंगलवार को पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

डीएम ने जवाहर नवोदय, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय व बृहद संरक्षण गौशाला का किया निरीक्षण

विजय द्विवेदी/वेलकम इन्डिया

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने नरायनपुर स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय और जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद कर पढ़ाई और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने नरायनपुर लक्ष्मणपुर स्थित बृहद संरक्षण गौशाला का भी जायजा लिया। गौशाला में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल सुधार के निर्देश दिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से पठन-पाठन की स्थिति, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। छात्रों द्वारा बताई गई समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने विद्यालय के खेल मैदान और पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने तथा विद्यार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा, जिससे बच्चों को अध्ययन और खेलकूद के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके बाद जिलाधिकारी ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय नरायनपुर, जिसे पूर्व में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के नाम से जाना जाता था, का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर छात्र-छात्राओं से बातचीत की और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही छात्रावास की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को विद्यालय की व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विद्यालयों के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बृहद संरक्षण गौशाला नरायनपुर लक्ष्मणपुर का निरीक्षण किया। यहां व्यवस्थाएं संतोषजनक न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। डीएम ने गौशाला में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने, पशुओं के समुचित रख-रखाव और जलभराव की समस्या का तत्काल समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

मिठाई और ढाबों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, छह नमूने जांच को भेजे

विजय द्विवेदी/वेलकम इन्डिया

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सोमवार को मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए रेस्टोरेंट, ढाबों और मिष्ठान प्रतिष्ठानों में छापेमारी एवं निरीक्षण की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के छह नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-।। अभय कुमार सिंह के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में खाद्य सचल दल ने सबसे पहले रानीगंज स्थित तिवारी ढाबा का निरीक्षण किया। टीम ने यहां से पकी हुई दाल और सरसों के तेल के नमूने लिए। इसके बाद देव भोग स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। खाद्य टीम ने पावर हाउस रानीगंज स्थित मिठा महल से खोया का नमूना संग्रहित किया। वहीं पृथ्वीगंज स्थित मनीराम स्वीट्स से भी खोया का नमूना जांच के लिए लिया गया। इसके अलावा जिला अस्पताल चौराहा स्थित सागर जलपान गृह से खोया बर्फी और खोया के नमूने संग्रहित किए गए। इस प्रकार टीम द्वारा कुल छह नमूने संग्रहित किए गए हैं। सभी नमूनों को खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। छापेमार कार्रवाई में रोशन सिंह, संतोष कुमार दूबे, डॉ. यादव संजय कुमार नन्हकू, शहाब उद्दीन सिद्दीकी और डॉ. शमशुन नेहा सहित खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे।

थ्रेशर के पट्टे में दुपट्टा फंसने से 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत

वेलकम इंडिया संवाददाता

बुगरासी। गांव किरयावली में मंगलवार को मक्का निकालते समय दर्दनाक हादसा हो गया। थ्रेशर के पट्टे में दुपट्टा फंसने से 18 वर्षीय युवती की गला दबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी प्रेमचंद के परिवार में घर पर थ्रेशर से मक्का निकाला जा रहा था। इसी दौरान उनकी 18 वर्षीय पुत्री रवीना का दुपट्टा अचानक थ्रेशर के पट्टे में फंस गया। देखते ही देखते दुपट्टा खिंचने से रवीना का गला दब गया। परिजनों ने तत्काल थ्रेशर बंद कर रवीना को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन उसे हायर सेंटर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रवीना ने दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि परिजन मृतका के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं।

कर्मचारियों के उत्पीड़न पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताई नाराजगी

अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी, सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के सम्मान और संगठन विस्तार का निर्णय

वेलकम इंडिया/संतोष कुमार सिंह

वाराणसी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को कोषागार कार्यालय स्थित सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने की, जबकि संचालन उपाध्यक्ष हरेंद्र यादव ने किया। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं, संगठन के विस्तार और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के सम्मान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पिछले वर्षों में संगठन के जिन पदाधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्होंने संगठन के लिए योगदान दिया है, उनका सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन को और मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों को कार्यकारिणी में शामिल कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया गया। अध्यक्षीय संबोधन में जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद के कुछ विभागों में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी के बावजूद कार्यरत कर्मचारियों पर लगातार कार्य का दबाव रहता है। ऐसे में मानसिक दबाव और उत्पीड़न से कर्मचारियों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं रुका तो परिषद लामबंद होकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। बैठक के अंत में जिला मंत्री श्याम राज यादव ने सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया।

बैठक में मंडल अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी, राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता, विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, सलाहकार एवं मार्गदर्शक मंडल के अशोक कुमार सिंह, प्रमोद श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, श्रीप्रकाश लाल, राज्य कर विभाग से कुमारी सुषमा भास्कर, स्वास्थ्य विभाग से गीता उपाध्याय एवं वेद प्रकाश सिंह, पशुपालन विभाग से हेमलता भारती, कृषि विभाग से प्रियंका गुप्ता, गया यादव, सुनील कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, नंदलाल गुप्ता, कुष्ठ विभाग से नीरज श्रीवास्तव, कोषागार से देवेंद्र राय एवं कमलेश सिंह, सिंचाई विभाग से अरविंद दूबे एवं अवधेश पांडेय, मनीष चौबे सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

बुलंदशहर (वेलकम इंडिया)। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे शातिर अभियुक्त प्रकाश भारती पुत्र उमेश भारती, निवासी ग्राम रामगढ़, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 641/2026, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था और वह इस मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस टीम ने 24 अगस्त को अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। आपराधिक इतिहास : प्रकाश भारती के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात में तीन मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मु0अ0सं0 09/2026 धारा 305/307(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 25/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 641/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रवि रतन सिंह, उपनिरीक्षक अमित पटेरिया, हेड कांस्टेबल गौरव कुमार, हेड कांस्टेबल बिजेन्द्र शर्मा, कांस्टेबल बलजोर सिंह एवं कांस्टेबल विशाल कुमार शामिल रहे।

50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने की समीक्षा, धीमी प्रगति पर नोटिस के निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

बुलंदशहर। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने मंगलवार को जनपद में 50 लाख रुपये से अधिक लागत से संचालित विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की परियोजनावार समीक्षा की। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने बताया कि जनपद में विभिन्न विभागों की कुल 89 परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें 22 परियोजनाएं अभी अनारम्भ हैं, जबकि 12 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जिलाधिकारी ने पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को संबंधित विभागों को हैंडओवर करने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों पर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कार्यदायी संस्था जल निगम नगरीय द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बारिश के मद्देनजर फिलहाल खुदाई का कार्य न किया जाए। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

यू.पी. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, निर्माण इकाई-नोएडा द्वारा जनपद में कराए जा रहे नौ निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि इनमें से एक निर्माण कार्य यूनिट-32 अलीगढ़ को हस्तांतरित किया गया है। कार्यदायी संस्था का जनपद में कार्यालय संचालित न होने के कारण निर्माण कार्यों की प्रगति प्रभावित होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित संस्था को पत्र भेजकर कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रकरण से शासन को भी अवगत कराने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में संचालित निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए। उन्होंने कार्यों की नियमित निगरानी और प्रगति में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री निशा ग्रेवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार दोहरे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

'रिश्ते ही पूंजी हैं' के एपिसोड-3 'पुष्पक' का भव्य प्रीमियर सम्पन्न

संस्कारों, रिश्तों और करियर के बीच संतुलन का संदेश लेकर युवाओं के बीच पहुंची प्रेरक कहानी

वेलकम इंडिया/संतोष कुमार सिंह

वाराणसी। लोकप्रिय मोटिवेशनल सीरीज 'रिश्ते ही पूंजी हैं' के एपिसोड-3 'पुष्पक–संस्कार से सफर तक' का भव्य प्रीमियर मंगलवार को अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पहड़िया-सारनाथ में आयोजित किया गया। प्रातः नौ बजे आयोजित प्रीमियर में करीब 200 छात्र-छात्राओं सहित शहर के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। महज 14 मिनट 45 सेकेंड के इस प्रेरणादायक एपिसोड ने दर्शकों को रिश्तों, संस्कारों और जीवन में इनके महत्व पर सोचने के लिए प्रेरित किया। विशेष रूप से जेन-जी और आज के युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस एपिसोड में रिश्तों, पारिवारिक संस्कारों और करियर के बीच संतुलन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी का उद्देश्य व्यस्त और डिजिटल होती जीवनशैली के बीच कमजोर पड़ते पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों को संस्कारों और संवेदनाओं की डोर से फिर जोड़ना है। कार्यक्रम में जय श्री कृष्णा फाउंडेशन के संस्थापक एवं मोटिवेशनल स्पीकर संजीव अग्रवाल ने कहा कि हमारे संस्कार ही हमारे पंख हैं। जब रिश्तों में समर्पण और सम्मान की उड़ाा होती है, तभी जीवन का पुष्पक उड़ान भरता है। उन्होंने कहा कि आज की जेन-जी डिजिटल दुनिया से तेजी से जुड़ रही है, लेकिन इसके साथ दिल के रिश्तों को मजबूत बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।

कार्यक्रम में जेएसके के सह-संस्थापक अरविंद जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन दिव्या अग्रवाल ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन अंकित लिल्हा ने किया। प्रीमियर शो को ह्यरिश्तों के देवदूतह्व मनीष गर्ग, ऋषि जायसवाल, विकास शुक्ला, शुभो घोष, प्रकाश भागचंदनी, धर्मेंद्र दुबे, प्रमोद गुप्ता, अंकित लिल्हा एवं साक्षी अपूर्व अग्रवाल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रजेश लोड, प्रदीप मल्होत्रा, डॉ. वीरेंद्र केसरी, सीए रश्मि केशेरवानी, सौम्या अग्रवाल, ऐश्वर्य अग्रवाल, नीरज पारीख, डॉ. शालिनी राणा, सुषमा अग्रवाल, संजीता अग्रवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अशोका इंस्टीट्यूट के करीब 200 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रीमियर में भाग लिया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अशोका इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन डॉ. अमित मौर्य और डायरेक्टर डॉ. सारिका श्रीवास्तव ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। जयपुर से पहुंचे विशेष अतिथि अशोक गर्ग ने भी एपिसोड की सराहना करते हुए टीम के प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम ने युवाओं के बीच यह संदेश देने का प्रयास किया कि आधुनिकता और सफलता की दौड़ के साथ रिश्तों एवं संस्कारों को साथ लेकर चलना ही जीवन को सार्थक बनाता है।

आयुर्वेदिक बोर्ड में 41 संदिग्ध पंजीयन का मामला गरमाया

डॉ. शैलेश राय ने सीबीआई जांच की मांग उठाई, रजिस्ट्रार समेत जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की मांग

वेलकम इंडिया/संतोष कुमार सिंह

वाराणसी। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में कथित रूप से 41 फर्जी चिकित्सक पंजीयन का मामला सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। बोर्ड के निवर्तमान उपाध्यक्ष डॉ. शैलेश कुमार राय ने मंगलवार को जगतगंज स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अथवा किसी सक्षम पुलिस एजेंसी से कराने की मांग की है। डॉ. शैलेश कुमार राय ने पत्रकारों को बताया कि वर्ष 2020 से अप्रैल 2022 तक बोर्ड में राज्य सरकार की ओर से नियंत्रक नियुक्त था, जबकि डॉ. अखिलेश वर्मा वर्ष 2017 से प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। उनका आरोप है कि इसी अवधि में कथित तौर पर पैसे लेकर कई फर्जी पंजीयन किए गए।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 में श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के नाम से 41 लोगों की बीएएमएस की अंकतालिका, प्रमाणपत्र, प्रोविजनल पंजीयन और हरियाणा बोर्ड का अनापत्ति प्रमाणपत्र कथित रूप से फर्जी तैयार किए गए। उनके अनुसार, इन दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन कराकर 41 लोगों का पंजीयन किया गया और वे इसके आधार पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। डॉ. राय के मुताबिक रामपुर निवासी फुरकान अली ने 16 जुलाई 2024 को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों से पांच कथित फर्जी पंजीयन की शिकायत की थी। इसके बाद अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में संबंधित राष्ट्रीय संस्था की टीम ने लखनऊ स्थित बोर्ड कार्यालय पहुंचकर जांच की। उनका दावा है कि शिकायत में बताए गए पांच पंजीयन के अलावा कुल 41 पंजीयन संदिग्ध पाए गए और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद इनके फर्जी होने की पुष्टि हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पंजीयनों के संबंध में बोर्ड की बैठक में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के बजाय रजिस्ट्रार ने 17 अप्रैल 2025 को स्वयं ही 41 पंजीयन निरस्त कर दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा गया, लेकिन उनके अनुसार मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. राय ने इसे जांच के बजाय मामले को दबाने का प्रयास बताया। डॉ. राय ने आगे आरोप लगाया कि प्रकरण की जानकारी सामने आने के बाद भी रजिस्ट्रार की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त 2026 को बोर्ड के संज्ञान में कथित फजीर्वाड़ा आने के बाद उन्होंने 10 अगस्त को बोर्ड की आकस्मिक बैठक बुलाने की पहल की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों से रजिस्ट्रार की भूमिका और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की।

उनका आरोप है कि इसी दौरान बोर्ड को भंग कर नियंत्रक नियुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई और चुनाव की घोषणा की गई, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। डॉ. राय ने दावा किया कि दबाव बढ़ने के बाद 22 अगस्त 2026 को 41 कथित फर्जी पंजीकृत चिकित्सकों के खिलाफ थाना हुसैनगंज, लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई, लेकिन इसमें शिकायत में नामजद रजिस्ट्रार और अन्य लोगों की भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया।

जांबाज दरोगा ने जलती कार से बचाई 3 जानें: भागूपुर पुल पर बड़ा हादसा, गश्त पर निकले एसआई 'अवनीश अग्निहोत्री' बने 'देवदूत'

वेलकम इंडिया/मयूर खान

आगरा। जनपद आगरा में पुलिस की वर्दी सिर्फ कानून लागू करने के लिए नहीं, बल्कि हर संकट में आम जनता के लिए ढाल बनकर खड़े रहने का नाम है। इस कहावत को थाना एत्मादपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर अवनीश अग्निहोत्री ने अपने अदम्य साहस और जांबाजी से सच कर दिखाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एत्मादपुर थाना क्षेत्र के भागूपुर पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां फिरोजाबाद से आगरा की तरफ आ रही एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और उसमें अचानक भीषण आग लग गई। कार के अंदर सवार लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया और वे अंदर ही फंस गए। घटना के समय थाना एत्मादपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर अवनीश अग्निहोत्री इलाके में गश्त पर निकले हुए थे। जैसे ही उनकी नजर धू-धू कर जलती कार पर पड़ी, वे बिना अपनी जान की परवाह किए तुरंत मौके पर पहुंचे। कार के अंदर से उठती चीख-पुकार सुनकर उन्होंने अकेले ही साहस का परिचय दिया और कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगर एसआई अवनीश अग्निहोत्री की तत्परता और जांबाजी न होती तो जलती कार में सवार तीनों लोगों की जान जा सकती थी। उन्होंने बिना समय गंवाए घायलों को तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपचार हेतु भिजवाया, जहां उनका इलाज जारी है। सब इंस्पेक्टर अवनीश अग्निहोत्री के इस अदम्य साहस और मुस्तैदी की स्थानीय लोगों और पुलिस महकमे में जमकर सराहना हो रही है। उनकी इस जांबाजी ने साबित कर दिया कि खाकी न सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने के लिए है, बल्कि हर विकट स्थिति में आम जनता की सुरक्षा के लिए सबसे पहले खड़ी रहती है।

एसआरएम आई एस टी दिल्ली-एनसीआर परिसर में प्रेरणा दिवस 2026 का भव्य आयोजन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली-एनसीआर परिसर, मोदीनगर में ईश्वरी ऑडिटोरियम में विश्वविद्यालय के माननीय संस्थापक कुलाधिपति डॉ. टी. आर. पारिवेंदर के जन्मदिवस के अवसर पर 'प्रेरणा दिवस 2026' का भव्य आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के नेतृत्व, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने एकत्रित होकर संस्थापक कुलाधिपति के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणादायी व्यक्तित्व तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके निरंतर योगदान का स्मरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रोमिल अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड, सेल्सफोर्स , रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना का आयोजन किया गया।

अतिथियों के सम्मान एवं अभिनंदन के बाद कार्यक्रम को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया गया। स्वागत संबोधन डॉ. धौम्या भट्ट, डीन, आईक्यू ए सी द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात डॉ. आर. पी. महापात्र, डीन ने अपना संबोधन दिया तथा डॉ. एस. विश्वनाथन, निदेशक, एसआरएम आई एस टी दिल्ली-एनसीआर परिसर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रेरणा दिवस समारोह के दौरान 'काटिंग द केक , शेयरिंग द जॉय ' थीम के अंतर्गत केक कटिंग समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन ने संस्थापक कुलाधिपति के जन्मदिवस की खुशी को सामूहिक उत्सव एवं पारिवारिक भावना से जोड़ दिया।

समारोह का प्रमुख आकर्षण मुख्य अतिथि रोमिल अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड, सेल्सफोर्स का प्रेरणादायी संबोधन रहा। इस अवसर पर सेल्सफोर्स के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 'एकेडेमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026' भी प्रदान किए गए।

इन पुरस्कारों के माध्यम से एसआरएम के 'शाइनिंग स्टार्स ' को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एक आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई, जिसने समारोह में उत्साह और उल्लास का वातावरण बनाया। समारोह के अंत में डॉ. शिवानी रोहिल्ला, हेड-सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया प्रेरणा दिवस 2026 का आयोजन केवल संस्थापक कुलाधिपति के जन्मदिवस का उत्सव नहीं था, बल्कि यह प्रेरणा, उत्कृष्टता, नवाचार, नेतृत्व और शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना का उत्सव भी रहा। इस अवसर ने एसआरएम आई एस टी की शैक्षणिक यात्रा में संस्थापक कुलाधिपति के दूरदर्शी विचारों, मूल्यों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को पुनः स्मरण करने का अवसर प्रदान किया।

विश्व बंधुत्व दिवस पर रक्तदान महाअभियान एवं रक्षाबंधन महोत्सव सम्पन्न

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राजयोग भवन आदर्श नगर, मोदीनगर के तत्वावधान में राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 19 वीं पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर विश्व बंधुत्व दिवस, रक्तदान महाअभियान एवं रक्षाबंधन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों, युवाओं एवं सामाजिक कार्यकताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद मोदीनगर के चेयरमैन विनोद वैशाली रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉ. अभिषेक चौधरी, ललित त्यागी (सभासद, आदर्शनगर मोदीनगर), गुलाब सिंह एवं सोनू सभासद उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित रक्तदान महाअभियान में कुल 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है रक्षाबंधन महोत्सव के अंतर्गत आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ योग एवं मुरली ज्ञान का आयोजन किया गया। ब्रह्माकुमारी बहनों ने रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व केवल भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि समाज में प्रेम, विश्वास, पवित्रता, सुरक्षा एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश भी देता है। इस अवसर पर बी.के. सुनीता दीदी (सेंटर इंचार्ज, मेरठ), बी.के. नीतू दीदी (सेंटर इंचार्ज, मोदीनगर), योगेंद्र शर्मा, अक्षय शर्मा, सुमित वर्मा, अभय, मनीषा 'शिखर', बी.के. कुंतेश, बी.के. वर्षा ,बी.के. आरती, बी.के. शालू सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

वित्तविहीन स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन का चुनाव संपन्न

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। जनपद गाजियाबाद मे संचालित यूपी बोर्ड के 155 इंटर कॉलेज के प्रबंधको वित्तविहीन स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया सम्पूर्ण हुई। चुनाव में अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, महासचिव विशाल सिंघल, कोषाध्यक्ष नवनीत शर्मा, सचिव ललित त्यागी व मीडिया प्रभारी अमित सम्मानिया, 5 उपाध्यक्ष 2 क्षेत्रीय अध्यक्ष 7 संगठन मंत्री 6 सह संगठन मंत्री सहित कुल 41 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। संस्था का संरक्षक मार्गदर्शन शिक्षाविद सतीश तेवतिया को निर्विरोध चुना गया।

यू वी कैन-ब्रिगिंग स्माइल्स फाउंडेशन द्वारा 126 जरूरतमंद बच्चों को जूते प्रदान किए गए

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। यू वी कैन-ब्रिगिंग स्माइल्स फाउंडेशन द्वारा संचालित 'चरण पादुका अभियान' के अंतर्गत दयावती मोदी जूनियर हाई स्कूल, ग्राम सैदपुर में जरूरतमंद बच्चों के लिए जूते उपलब्ध कराने का सेवा कार्य किया गया। इस अवसर पर 126 जरूरतमंद बच्चों को जूते प्रदान किए गए। संस्था की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा ने कहा कि 'चरण पादुका अभियान' केवल जूते उपलब्ध कराने का प्रयास नहीं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के आत्मसम्मान, सुविधा और बेहतर भविष्य की दिशा में एक छोटा-सा सार्थक कदम है। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहेगा। इस सेवा कार्य में सहयोग के रूप में 31 जोड़ी जूते साईं सन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तथा 21 जोड़ी जूते संस्था के सदस्य पवन त्यागी द्वारा अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर सुनीता शर्मा , विशाल माहेश्वरी, रौनक दीप गांधी, मनीष कौशल, सचिन वधावन, ईशान गिरी, गुरदीप सिंह एवं आशुतोष शर्मा ने अभियान में अपना सक्रिय योगदान दिया। बच्चों के जूतों के नाप लेने के कार्य में गुरदीप सिंह एवं विशाल वर्मा ने विशेष सहयोग किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती मीनाक्षी शर्मा सहित विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं ने भी इस सेवा कार्य में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस आयोजन के साथ 'चरण पादुका अभियान' ने 5,651 बच्चों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया। संस्था का उद्देश्य सेवा, संवेदना और सहयोग की भावना के साथ ऐसे बच्चों के जीवन में छोटी-सी खुशी और आत्मविश्वास की बड़ी मुस्कान लाना है। 'एक जोड़ी जूते केवल कदमों को राह नहीं देते,वे किसी बच्चे के सपनों को आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं।'

दीपक चौधरी बढ़ायला ने अपने साथियों के साथ भाजपा का दामन थामा

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। जगन्नाथ इंस्टीट्यूट में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम में आधा दर्जन से अधिक लोगों में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की ।कार्यक्रम में दीपक चौधरी बढ़ायला (ऋषभ विहार) व उनके साथी रजनीश चौधरी, विपिन चौधरी, नितिन चौधरी, वैभव चौधरी आदि लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास अग्रवाल , शिक्षक एमएलसी चंद शर्मा , भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैन पाल, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल , जिला महामंत्री रामकुमार त्यागी, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार , प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चौधरी डायमंड , जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी, कोऑपरेटिव सोसायटी अध्यक्ष नरेश अमराला, नगर महामंत्री तृषा गोस्वामी , भाजपा नेता देवराज शर्मा, पप्पन शर्मा व अन्य पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

खेल चोटों के इलाज की तकनीक से रूबरू हुए विद्यार्थी, टेपिंग और ड्राई नीडलिंग का लिया प्रशिक्षण

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। दिल्ली मेरठ रोड़ स्थित आईटीएस फिजियोथैरेपी कॉलेज, मुरादनगर में फिजियोकॉन-2026 के अंतर्गत मंगलवार को 'खेल संबंधित चोटों में टेपिंग तकनीक एवं ड्राई नीडलिंग' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को खेल के दौरान होने वाली विभिन्न चोटों की पहचान, उपचार और पुनर्वास में उपयोगी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञ ने विद्यार्थियों को तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराने के साथ उनका अभ्यास भी कराया, जिससे विद्यार्थियों के व्यावहारिक कौशल में वृद्धि हुई। कार्यशाला के अवसर पर आईटीएस-द एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन डॉ. आरपी चड्ढा और वाइस चेयरमैन अर्पित चड्ढा ने विशेषज्ञ डॉ. अमित दुबे का स्वागत किया। वाइस चेयरमैन अर्पित चड्ढा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को उपचार की नई तकनीकों को समझने के साथ उनका व्यावहारिक अभ्यास भी करना चाहिए। संस्थान का प्रयास है कि विद्यार्थियों को अनुभवी विशेषज्ञों

से सीखने और अपने कौशल को निखारने के अधिक से अधिक अवसर मिलें। कार्यशाला के विशेषज्ञ डॉ. अमित दुबे खेल फिजियोथैरेपिस्ट हैं और मुंबई इंडियंस की आईपीएल टीम से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञ रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों के दौरान होने वाली विभिन्न प्रकार की चोटों, उनके उपचार और पुनर्वास की प्रक्रिया में टेपिंग एवं ड्राई नीडलिंग की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. दुबे ने अलग-अलग प्रकार की चोटों में टेप लगाने की सही विधि का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया।

उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि चोट की प्रकृति और शरीर के प्रभावित हिस्से के अनुसार तकनीक का चयन किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों ने स्वयं टेपिंग का अभ्यास किया और विशेषज्ञ से अपनी शंकाओं का समाधान कराया। कार्यशाला में ड्राई नीडलिंग के उपयोग और उससे जुड़ी आवश्यक सावधानियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

विशेषज्ञ ने विद्यार्थियों को बताया कि उपचार प्रक्रिया में किसी भी तकनीक का प्रयोग उचित प्रशिक्षण, मूल्यांकन और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने तकनीक को समझने के साथ उसके व्यावहारिक पहलुओं को भी करीब से देखा। संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. एम. थगराज ने कहा कि खेलों में चोट लगने की स्थिति में फिजियोथैरेपिस्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार करने में मदद करते हैं और उनके व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत करते हैं।

मिठाई में मिलावट की रेकी कर रहा खाद्य सुरक्षा विभाग, 10 टीमें मुस्तैद

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर्व पर लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने जिले में 10 विशेष टीमें गठित की हैं, जो मिठाई बनाने वाले कारखानों और बड़े प्रतिष्ठानों की लगातार रेकी कर रही हैं। टीमें खोया, रसगुल्ला, घेवर समेत विभिन्न मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के साथ उनके नमूने भी ले रही हैं। लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। मिलावटी खाद्य सामग्री को दूसरे जनपदों से गाजियाबाद में खपाने की कोशिश पर रोक लगाने के लिए विभाग ने शहर की सीमाओं पर भी टीमों की रोस्टर के आधार पर तैनाती की है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल मिठाई की दुकानों तक कार्रवाई सीमित रखना नहीं, बल्कि मिलावटी खाद्य सामग्री के स्रोत और आपूर्ति तंत्र तक पहुंचना है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपने-अपने क्षेत्रों में बड़े स्तर पर मिठाई बनाने वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों की सूची तैयार की है। इसी सूची के आधार पर टीमें संबंधित प्रतिष्ठानों की रेकी कर रही हैं। किसी प्रतिष्ठान में मिलावट की सूचना मिलने अथवा संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर टीम मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई कर रही है। जांच के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए जा रहे हैं। साथ ही प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रखरखाव और निर्माण प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यदि किसी प्रतिष्ठान में गंभीर स्तर पर गंदगी या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़े के कारण विभाग ने विशेष रूप से उन खाद्य पदार्थों पर नजर बढ़ाई है, जिनकी बिक्री इस दौरान अधिक होती है। खोया, रसगुल्ला, घेवर समेत विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के नमूने लिए जा रहे हैं। विभाग का मानना है कि त्योहार के दौरान बढ़ती मांग का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी अधिक मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर सकते हैं। जिला अभिहित अधिकारी सुरेश मिश्रा ने बताया कि विभाग लगातार मिठाई बनाने वाले कारखानों और बड़े प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहा है।

संभव में नगर आयुक्त ने सुनीं शहरवासियों की फरियादें, 21 शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम की ओर से मंगलवार को संचालित 'संभव' जनसुनवाई में नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने लोगों की शिकायतें सुनीं। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 21 संदर्भ प्राप्त हुए। नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने और मौके पर टीम भेजकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों में निर्माण विभाग से छह, उद्यान विभाग से तीन, कर विभाग से चार, संपत्ति विभाग से दो, जलकल विभाग से पांच और अतिक्रमण से संबंधित एक संदर्भ शामिल रहा। नगर आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को केवल दर्ज करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके समाधान की प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। जनसुनवाई के दौरान अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश सहित संपत्ति, जलकल, प्रकाश और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई में

विजयनगर क्षेत्र से आए एक शिकायतकर्ता ने जलकल विभाग से संबंधित समस्या नगर आयुक्त के सामने रखी। शिकायत सुनने के बाद नगर आयुक्त ने संबंधित अवर अभियंता मयंक मिश्रा को मौके पर बुलाकर समस्या के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलकल विभाग से जुड़ी शिकायतों पर विशेष तेजी से कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को पेयजल और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित परेशानी का लंबे समय तक सामना न करना पड़े।

संभव में प्राप्त अन्य शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर टीम भेजकर समस्या के समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई। नगर आयुक्त ने अधिकारियों से कार्रवाई की प्रगति पर भी नजर रखने को कहा। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि संभव जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। जिन समस्याओं का संबंध एक से अधिक विभागों से है, उनमें संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर कार्रवाई पूरी की जाए। उन्होंने जोनल प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। जोनल प्रभारी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करेंगे, ताकि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए नगर निगम कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक संदर्भ को गंभीरता से लिया जाए।

लोनी में प्रदूषण पर बड़ी कार्रवाई: 25 अवैध फैक्ट्रियां सील, बिजली कनेक्शन काटे

=कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। लोनी तहसील क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 अवैध धातु गलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सीलिंग और विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉदड़ के आदेश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम लोनी दीपक सिंघनवाल के निदेर्शानुसार सोमवार, 25 अगस्त को सात संयुक्त टीमों ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया।

ग्राम बहटा हाजीपुर, सेवाधाम, अमित विहार, प्रेमनगर, कृष्णा नगर, अंकित विहार और टीला शहबाजपुर में केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विद्युत, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने कार्रवाई की।

अभियान का नेतृत्व तहसीलदार लोनी, तहसीलदार मोदीनगर एवं नायब तहसीलदारों ने किया। एसडीएम दीपक सिंघनवाल ने स्पष्ट किया कि लोनी क्षेत्र में किसी भी हालत में अवैध प्रदूषणकारी इकाइयों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा युवक, संदिग्ध हालात में मौत; छह ससुरालियों पर केस

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। पत्नी को लेने ससुराल आए फरीदाबाद निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पहचान फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र के झारसेतली निवासी मनोज सोलंकी के रूप में हुई है। उसके पिता समय सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मनोज का अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष से पिछले करीब छह-सात महीने से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बीच 27 जून को मनोज अपनी पत्नी को लेने क्रॉसिंग रिपब्लिक के सैन विहार स्थित ससुराल पहुंचा था। मृतक के पिता के अनुसार, 27 जून की रात करीब नौ से साढ़े नौ बजे के बीच मनोज ने अपने परिचित अरुण कुमार को फोन किया।

आरोप है कि फोन पर मनोज ने बताया कि ससुराल वालों ने उसे कुछ खिला दिया है और उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई है। मनोज की बात सुनने के बाद अरुण ने उसके स्वजन को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर परिवार के लोग क्रॉसिंग रिपब्लिक के सैन विहार स्थित गली नंबर छह में पहुंचे। वहां मनोज ससुराल के मकान के बाहर गंभीर हालत में पड़ा मिला। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया। मनोज को परिजन उपचार के लिए जीटीबी अस्पताल दिल्ली लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। हालांकि हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सक उसे बचा नहीं सके। 28 जून की सुबह करीब चार बजे उपचार के दौरान चिकित्सकों ने मनोज को मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत के बाद पिता समय सिंह ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में शिकायत देकर ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का बंधन, इको-फ्रेंडली राखियों ने दिया खास संदेश

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। नगर निगम गाजियाबाद द्वारा इको-फ्रेंडली राखी फेस्टिवल का आयोजन कर रक्षाबंधन के पर्व को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संदेश से जोड़ा गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने Reduce, Reuse और Recycle की अवधारणा पर आधारित सामग्री से स्वयं आकर्षक राखियां तैयार कीं।

इस अवसर पर महिला स्वच्छता प्रहरियों ने नगर आयुक्त महोदय को राखी बांधकर स्वच्छता के प्रति निरंतर सहयोग और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। नगर आयुक्त ने भी राखी की परंपरा निभाते हुए सभी प्रतिभागियों को मिष्ठान एवं उपहार भेंट किए।

कार्यक्रम के माध्यम से संदेश दिया गया कि त्योहारों की खुशियों के साथ प्रकृति और स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। स्वच्छता के इस बंधन के साथ सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

कनावनी के किसानों का बड़ा ऐलान: 30 अगस्त को महापंचायत, आंदोलन होगा और तेज

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। ग्राम कनावनी के किसानों का अपनी मांगों को लेकर धरना सोमवार को 12वें दिन भी जारी रहा। किसानों की पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि ईद और रक्षाबंधन के मद्देनजर 30 अगस्त को धरना स्थल पर महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसमें आसपास के गांवों के किसान, जनप्रतिनिधि और किसान प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

किसानों ने कहा कि यदि GDA कनावनी गांव की जमीन ले रहा है तो मुआवजा भी गांव की प्रचलित दर के अनुसार दिया जाना चाहिए। साथ ही आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लेने की मांग उठाई गई।

किसानों ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो महापंचायत में आंदोलन को बड़े और निर्णायक स्तर पर ले जाने की रणनीति तय की जाएगी। पंचायत में चतर सिंह नागर, अजब सिंह, एमएस नागर, राजेंद्र नागर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

दनकौर में इरद का शक्ति प्रदर्शन, आकाश आनंद के निशाने पर 2027 चुनाव

कपिल चौहान

ग्रेटर नोएडा (वेलकम इंडिया)। बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए जेवर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी अभियान का आगाज करने की तैयारी कर ली है। इसी क्रम में इरद के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मंगलवार को दनकौर पहुंचे, जहां वह पार्टी नेता सतवीर नागर के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर इरद कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आयोजन स्थल पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के संबोधन के जरिए पार्टी जेवर विधानसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक ताकत का संदेश देगी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दनकौर की यह जनसभा BSP के लिए अहम मानी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस आयोजन से क्षेत्र में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और चुनावी अभियान को मजबूती मिलेगी।

विचाराधीन बंदी की मौत की न्यायिक जांच शुरू, 29 अगस्त तक पेश कर सकेंगे साक्ष्य

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। विचाराधीन बंदी मनीष पुत्र लक्ष्मण की उपचार के दौरान हुई मृत्यु के मामले में न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जांच अधिकारी एवं अपर सिविल जज (सीडी)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-3, गाजियाबाद सुमन सौलंकी ने सर्वसाधारण से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील की है। मनीष, निवासी मडावली, थाना मण्डावली, पूर्वी दिल्ली की 14 जून 2026 को लोकनायक जयप्रकाश चिकित्सालय, नई दिल्ली में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों की जांच संख्या 1/2026 न्यायालय अपर सिविल जज (सीडी)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-3, गाजियाबाद में लंबित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति के पास मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य हो तो वह 29 अगस्त 2026 तक न्यायालय समय में कक्ष संख्या-13, प्रथम तल, जिला एवं सत्र न्यायालय, गाजियाबाद में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

1298 फ्लैट, चार हजार जिंदगियां और जर्जर इमारतें, गंगा-यमुना-हिंडन अपार्टमेंट में हादसे का डर

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा-यमुना-हिंडन अपार्टमेंट की जर्जर होती इमारतों ने यहां रहने वाले करीब चार हजार लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 1298 फ्लैटों वाली इस सोसायटी के कई भवनों में जगह-जगह प्लास्टर उखड़ चुका है और दीवारों व कॉलम से सरिया बाहर दिखाई देने लगा है। फ्लैटों के बाहर बने छज्जे भी जर्जर होकर टूटने लगे हैं। ऐसे में निवासियों को हर समय किसी बड़े हादसे का डर सता रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत और रखरखाव का काम नहीं कराया गया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की भवन रखरखाव समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार, भवनों की मरम्मत समेत कई मूलभूत कार्य लंबे समय से लंबित हैं। उनका कहना है कि सोसायटी की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन समय पर स्थायी समाधान नहीं होने से अब कई हिस्से सुरक्षा के लिहाज से चिंता का कारण बन गए हैं। सोसायटी के कई भवनों की दीवारों और कॉलम से प्लास्टर झड़ चुका है। कई स्थानों पर निर्माण सामग्री के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया है, जिससे भवनों के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फ्लैटों के बाहर बने छज्जे भी जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं और कुछ हिस्सों में टूट-फूट शुरू हो चुकी है। इसके अलावा प्लंबिंग शाफ्ट के ऊपर बने रूफटॉप की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। एसोसिएशन का कहना है कि इन हिस्सों की समय पर मरम्मत नहीं हुई तो बारिश और मौसम के प्रभाव से स्थिति और खराब हो सकती है। निवासियों की मांग है कि भवनों की तकनीकी जांच कराकर जरूरी मरम्मत का काम जल्द कराया जाए।

लूटकांड का बड़ा खुलासा: मुठभेड़ के बाद पांच आरोपी गिरफ्तार, 10.05 लाख रुपये बरामद

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। वेव सिटी थाना पुलिस ने 24.85 लाख रुपये की सनसनीखेज लूट का बड़ा खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोचा गया, जबकि तीन अन्य आरोपियों को बाद में लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 10.05 लाख रुपये से अधिक नकदी, दो अवैध तमंचे, चार जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की काले रंग की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है।

पुलिस के अनुसार 22 अगस्त को दिल्ली-मेरठ रोड पर हाईटेक कॉलेज के सामने बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति की गाड़ी ओवरटेक कर रुकवाई और तमंचे के बल पर 24.85 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए थे। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 500 से 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और घटनास्थल के आसपास के बीटीएस डाटा व मोबाइल लोकेशन का विश्लेषण किया।

25 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद आईएमएस कॉलेज कट के पास हुई मुठभेड़ में आसिफ और सद्दाम गिरफ्तार किए गए। बाद में आस मोहम्मद, ओसामा और नदीम को भी उस्मानगढ़ी की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस फरार रकम और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है।

पुष्टाहार से बने पौष्टिक व्यंजनों की कुकिंग प्रतियोगिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिखाया हुनर

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच पुष्टाहार (टीएचआर) से पौष्टिक व्यंजन तैयार करने की कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ ने प्रतिभागियों के व्यंजनों का स्वाद चखा और उनके प्रयासों की सराहना की।

समस्त विकास खंडों एवं शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केवल पुष्टाहार और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों से विभिन्न पौष्टिक व्यंजन तैयार किए।

सीडीओ ने निर्देश दिए कि ऐसी रेसिपी की प्रदर्शनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावक बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों में भी लगाई जाए, ताकि लोगों को पुष्टाहार के महत्व और पौष्टिक व्यंजन बनाने के प्रति जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीता चंद्रा, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकाएं उपस्थित रहीं।

भाजपा कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह, बलप्रीत सिंह ने किया कुंवर बासित अली का अभिनंदन

कपिल चौहान

नई दिल्ली (वेलकम इंडिया)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर मंगलवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर बासित अली के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सरदार बलप्रीत सिंह विशेष रूप से शामिल हुए।

सरदार बलप्रीत सिंह ने कुंवर बासित अली को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कुंवर बासित अली का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी और अल्पसंख्यक समाज के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के उत्थान को नई गति मिलेगी और संगठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि कुंवर बासित अली जमीन से जुड़े नेता हैं, जिन्होंने अपना जीवन पार्टी, समाज और देश सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने भाजपा एवं एनडीए सरकार की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। बलप्रीत सिंह ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और अधिक मजबूत होगा।

त्योहारों से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा, 10 क्विंटल रसगुल्ले नष्ट

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को विभाग की तीन टीमों ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। करीब दो घंटे तक चली कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा रहा। छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ले बरामद किए। आशंका जताई गई कि इन्हें तैयार करने में मानकों के विपरीत सामग्री अथवा केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो सकता है।

राकेश कुमार मिश्रा, खाद्य अधिकारी

खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बरामद रसगुल्लों को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीमों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के चार नमूने भी जांच के लिए लिए हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद मिलावट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

खाद्य विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर मिठाई और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि मिलावटी या मानकों के विपरीत खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साइबर अपराध पर लगेगी और मजबूत लगाम, नए थाना भवन निर्माण का शिलान्यास

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस थानों एवं अन्य भवनों के जीर्णोद्धार और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मंगलवार, 25 अगस्त 2026 को थाना साइबर क्राइम के नए भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। नए भवन के निर्माण से साइबर अपराधों की जांच और पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में और मजबूती मिलेगी।

शिलान्यास कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध केशव कुमार चौधरी, पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध पीयूष कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त थाना भवन साइबर अपराधों से निपटने में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायक साबित होगा। कमिश्नरेट में पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य लगातार जारी है।